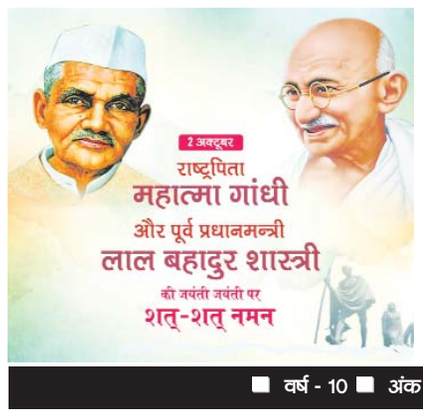


दैनिक
रेवांचल टाइम्स
निष्पक्ष, निर्भीक एवं सत्य का प्रवर्तक

Revanchal Times
7509202320
@revanchal_times
revanchaljabalpur@gmail.com
revanchaltimes_

■ वर्ष - 10 ■ अंक - 197 ■ मंडला, शुक्रवार 2 अक्टूबर 2026 ■ पृष्ठ-8 ■ मूल्य-1 रूपये ■ विक्रम संवत् 2083 ■ www.revanchaltimes.com RNI. Reg. No MPHIN/2016/69877

UPSC के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी बोले

युवाओं के भविष्य के लिए समय पर पूरी हों भर्ती परीक्षाएं



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से कहा है कि वह अपनी परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में चल रहे सुधारों को लागू करे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परीक्षाओं का युवा उम्मीदवारों के भविष्य पर सीधा असर पड़ता है और चेतावनी दी कि देरी से बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में वढरउ के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए, ढट मोदी ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालना चाहिए और समय की निश्चितता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।

मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ.एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए। यह हमारे युवाओं के भविष्य से जुड़ी है। कुछ महीनों की देरी भी युवाओं के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इसलिए, परीक्षा प्रणाली को समय की निश्चितता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। वढरउ की 100 साल की विरासत को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने लाखों युवा भारतीयों के बीच इस संस्था के प्रति अटूट भरोसे का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि आज का यह मौका वढरउ के 100 साल पूरे होने और इसकी शानदार विरासत का जश्न मनाने का है। यह जश्न हर साल लाखों युवाओं की उम्मीदों और सपनों को दशार्ता है। यह जश्न उस भरोसे को भी दिखाता है जो हर भारतीय इस संस्था पर करता है।

पीएम मोदी ने कहा कि पिछली एक सदी में पीढ़ियों, सरकारों, टेक्नोलॉजी और सिलेबस में बदलाव के बावजूद वढरउ पर लोगों का भरोसा मजबूत बना हुआ है और यह एक बड़ी संपत्ति है। उन्होंने भारत के विकास के लिए आने वाले 20 से 25 सालों को बहुत अहम बताया और कहा कि वढरउ और राज्य लोक सेवा आयोगों की भूमिका ऐसे युवाओं को चुनने में बहुत जरूरी है जो एक विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने जोर देकर कहा कि भर्ती प्रक्रिया दो मुख्य पैमानों पर आधारित होनी चाहिए: राष्ट्र पहले और नागरिक पहले। उन्होंने कहा कि ये वे दो पैमाने हैं जिनके आधार पर हर चयन को परखा जाना चाहिए। इसके अलावा, पीएम मोदी ने ऐसी परीक्षाओं की जरूरत पर जोर दिया जो उम्मीदवारों को न सिर्फ. एकेडमिक जानकारी के आधार पर परखें, बल्कि पब्लिक सर्विस में आने के उनके मकसद को भी देखें। उन्होंने कहा कि हमें पब्लिक सर्विस में ऐसे युवाओं को लाने की जरूरत है जो पब्लिक सर्विस की ओर आकर्षित हों, न कि सिर्फ. सरकारी पद की ओर। इसलिए, यह जरूरी है कि भर्ती परीक्षा में न सिर्फ.यह देखा जाए कि उम्मीदवार को कितनी जानकारी है, बल्कि यह भी देखा जाए कि युवा सिविल सर्विस में क्यों शामिल होना चाहते हैं।

राहुल गांधी बालाघाट दौरा

मृत आदिवासी बच्चों के परिवारों से मिले मप्र का हर पांचवां नागरिक आदिवासी



बालाघाट। राहुल गांधी ने गुरुवार को बालाघाट के बिरसा ब्लॉक के जगला गांव में बैगा आदिवासियों से जमीन पर बैठकर मुलाकात की। वे उन बैगा आदिवासी बच्चों के परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, जिनकी बीमारी के चलते मौत हुई। राहुल से मिलने के लिए आसपास के गांवों के डेढ़ हजार लोग पहुंचे हैं। इससे पहले रास्ते में राहुल ने माटे प्राथमिक शासकीय स्कूल में बच्चों से 15 मिनट मुलाकात की। उनसे मिड डे मील के बारे में जाना। बालाघाट जिले में पिछले 3 महीनों में कुपोषण और मलेरिया से 32 आदिवासी बच्चों की मौत हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि यह संख्या ज्यादा है। सरकार आंकड़े छुपा रही है। उधर, बीजेपी ने इस दौरे को राजनीतिक माइलेज लेने की कवायद बताया है। मध्य प्रदेश की आबादी में आदिवासियों की हिस्सेदारी 21.1% है, यानी हर पांचवां व्यक्ति। इसका असर चुनाव में भी दिखता है। विधानसभा की 230 सीटों में 47 रळ के लिए आरक्षित हैं, जबकि 37 अन्य सीटों पर भी आदिवासी वोट अहम माना जाता है। यानी कुल 84 सीटों पर इसका असर है। लोकसभा की 29 सीटों में 6 रळ के लिए आरक्षित हैं।

सुप्रिया बोलीं- राहुल गांधी हमेशा अडिग : कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- इस देश में जिसके साथ भी अन्याय होता है, वहां उनके साथ एक ही आदमी खड़ा है। हमेशा, हर वक्त, अडिग - राहुल गांधी आज नेता विपक्ष बालाघाट जा रहे हैं, जहां 30 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई और इखढ सरकार के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। हर बात का हिसाब होगा।

राहुल ने बच्चों से मध्याह्न भोजन पर बात की : राहुल महाराष्ट्र के बिरसी एयरपोर्ट से दोपहर 12.02 बजे सड़क मार्ग से रवाना हुए थे। वे रजेगांव, सालेटेगा, कोसमी बायपास से भरवेली, सोनेवानी, बिठली होते हुए ग्राम जगला पहुंचेंगे। उनका काफिला ग्राम माटे प्राथमिक शासकीय स्कूल में रुका, जहां राहुल ने बच्चों से मध्याह्न भोजन पर बात की। यहां करीब 15 मिनट रुके।

भारत-पाकिस्तान में होगा एशियन गेम्स फाइनल

टीम इंडिया ने श्रीलंका को 124 रन से हराया; ईशान की फिफ्टी, वैभव ने 38 रन बनाए



नई दिल्ली। भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराकर एशियन गेम्स के फाइनल में जगह बना ली है। अब शनिवार को गोल्ड के लिए भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह पहला मौका है जब ये दोनों टीमें एशियन गेम्स में क्रिकेट मुकाबले में आमने-सामने होंगी। भारत ने जापान के निशिन में खेले गए सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम 9.5 ओवर में 45 रन पर ऑलआउट हो गई। श्रीलंका के 6 बल्लेबाज खाता नहीं खोल सके। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट झटके। 3 बल्लेबाज रनआउट हुए। ईशान किशन ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने भी 21 गेंदों पर 38 रन बनाए। भारत ने श्रीलंका पर टी-20 क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया। पिछली सबसे बड़ी जीत 93 रन की थी, जो 2017 में कटक में मिली थी।

पाकिस्तान ने बांग्लादेश से जीता 13-13 ओवर का मैच : पाकिस्तान ने मेंस क्रिकेट के सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। यह मैच बारिश से प्रभावित हुआ। इसे 13-13 ओवर का कर दिया गया था। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 111 रन बनाए। पाकिस्तान ने 11.3 ओवर में 4 विकेट पर जीत हासिल कर ली।

'कौन भारतीय और कौन नहीं, इसकी पहचान जरूरी' आरएसएस ने दोहराई देशभर में आरएसएस कराने की मांग



नई दिल्ली। देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और जनगणना को लेकर चल रही चर्चा के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने एक बार फिर पूरे देश में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (आरएसएस) लागू करने की पुरजोर मांग उठाई है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह बिल्कुल साफ होना चाहिए कि देश में कौन असली भारतीय नागरिक है और कौन नहीं?

कार्यक्रम के दौरान सुनील आंबेकर ने दो टूक कहा कि अगर किसी को एनआरसी की प्रक्रिया पर कोई भी आपत्ति है, तो उनके लिए अदालत और कानून के रास्ते हमेशा खुले हैं। लेकिन सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए किसी भी गैर-नागरिक को भारतीय नागरिक मान लेना किसी भी कीमत पर सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़े गए गैर-नागरिकों की पहचान करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान संघ के प्रचार प्रमुख ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का समर्थन करते हुए कहा कि पड़ोसी देशों से भारत आए जो लोग उअअ के तहत नागरिकता के पात्र हैं, उन्हें प्रक्रिया के तहत नागरिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने पड़ोसी देशों में अब भी पीछे छूट गए एससी/एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे को भी गंभीरता से उठाने की बात कही।

अवैध प्रवास पिछली सरकार का किया घेराव

अपने संबोधन में आगे आंबेकर ने अवैध घुसपैठ और प्रवास के मुद्दे पर पिछली सरकारों का घेराव भी किया। उन्होंने कहा कि इस गंभीर समस्या को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। उन्होंने साल 1983 के 'इलीगल माइग्रेंट्स एक्ट' का विशेष रूप से जिक्र किया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया था।

9/11 जैसा हमला होने से बचा लिया', पीएम मोदी ने की फ्लाईदुबई के जांबाज कैप्टन स्मित मछार की तारीफ

नई दिल्ली। दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में बीते दिन हुई घटना में कैप्टन स्मित ने साहस दिखाते हुए सैकड़ों यात्रियों की जान बचाई। अब उनके साहस की दुनिया सराहना कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर कैप्टन स्मित की बहादुरी को सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीएससी के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, "कल हुई घटना में भारत के कैप्टन स्मित ने अद्भुत धैर्य, सूझ-बूझ और साहस का परिचय दिया। सचमुच, जैसा कि आज इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा की एक भारतीय ने 9/11 जैसी त्रासदी को होने से रोक दिया।" प्रधानमंत्री मोदी आगे कहा, "स्मित की इस उपलब्धि पर हमें गर्व है। आज मैंने उनके पिता भूपेंद्र, उनकी मां गीता और उनकी पत्नी सोनल से भी बात की। अभी उनका इलाज चल रहा है। आज पूरी दुनिया को उन पर गर्व है। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि वे स्मित की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और स्मित को सलाम करें, जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया है।"



सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को झटका

टीएमसी के चार बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने से किया इनकार



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) गुट को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पार्टी ने अपने चार डेबिट-फ्रीज किए गए बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति मांगी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें पहले इस मांग को ठुकरा दिया गया था। मामले में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की बेंच ने कहा कि चूंकि चुनाव आयोग ने पार्टी का चुनाव चिह्न फ्रीज कर दिया है और खातों में मौजूद फंड का असली हकदार कौन है, यह बड़ा सवाल अभी भी अदालत में विचाराधीन है, इसलिए वे इस मामले की गहराई में नहीं जाएंगे।

कलकत्ता हाईकोर्ट को सुनवाई में तेज लाने को कहा : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहते और अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं हैं। हम कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह इस मामले की सुनवाई में तेजी लाए।

बता दें कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से पब्लिक सेक्टर के बैंकों में फ्रीज किए गए अपने चार खातों को चलाने की अनुमति मांगी थी। पार्टी का तर्क था कि इन खातों को फ्रीज करने से जुड़ी एफआईआर में प्रक्रियागत कमियां थीं।

ऐसे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीते 27 अगस्त को अपने आदेश में उन चार बैंक खातों जिनमें करीब 804 करोड़ रुपये हैं को चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। अदालत का मानना था कि ऐसी राहत देने से उसका वह पिछला आदेश कमजोर हो जाता, जिसमें पार्टी को केवल अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने की छूट दी गई थी।

ईडी की कार्रवाई और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप

दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। ईडी का आरोप है कि कोलकाता स्थित 'केयरवेल एविएशन' के जरिए 160 करोड़ रुपये के पार्टी फंड की हेराफेरी की गई है। इसी जांच के तहत ईडी ने एचडीएफसी बैंक में टीएमसी के तीन खातों में मौजूद 440 करोड़ रुपये फ्रीज किए हैं।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य पर प्रयागराज में केस

ब्राह्मण समाज पर दिए बयान के खिलाफ याचिका, कहा था- हम चौबे-दीक्षित परिवारों में बेटियां नहीं देते



प्रयागराज। रामभद्राचार्य पर आरोप है कि उन्होंने वृंदावन में ब्राह्मण समाज की कुछ उप-जातियों पर विवादित बयान दिया। तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ प्रयागराज कोर्ट में केस चलेगा। रामभद्राचार्य के एक बयान के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बयान में जगद्गुरु ने कहा था- ऊंच कुल के ब्राह्मण अपनी बेटियां उपाध्याय, चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठकों को नहीं देते, क्योंकि हम इन्हें अधम मानतें हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि रामभद्राचार्य की लोग पूजा करते हैं। वृंदावन में भागवत कथा के दौरान दिए उनके बयान के बाद उपाध्याय समाज को लोग बुरी नजर से देखने लगे। लड़के-लड़कियों की शादी में रुकावट आने लगी है। रामभद्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। याचिकाकर्ता रमेश उपाध्याय भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रयागराज जिला अदालत ने गुरुवार को जगद्गुरु रामभद्राचार्य को नोटिस जारी कर 12 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा।

भारत-यूएई के बीच समुद्र में तेल पाइपलाइन की तैयारी

होर्मुज संकट के बीच विकल्प की तलाश; भारत 88% कच्चा तेल आयात करता है



नई दिल्ली। होर्मुज संकट के बीच भारत ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहा है। इसके तहत भारत और यूएई के बीच समुद्र के नीचे तेल और गैस पाइपलाइन बिछाने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूएई के विदेश व्यापार मंत्री थानी बिन अहमद अल जेउदी से मुलाकात के बाद इसकी पुष्टि की। सरकार ने ओमान-यूएई से भारत तक समुद्र के नीचे पाइपलाइन परियोजना को प्राथमिकता में रखा है। मिडिल ईस्ट टू इंडिया डीप-वॉटर पाइपलाइन के तहत पाइपलाइन ओमान और यूएई के तट से शुरू होकर अरब सागर के नीचे से गुजरते हुए गुजरात और महाराष्ट्र के तट तक पहुंच सकती है।

पहले सिर्फ गैस पाइपलाइन की थी योजना : जून में सरकार ने इस परियोजना को निजी प्रोजेक्ट बताया था। शुरूआत में इसमें सिर्फ गैस पाइपलाइन की योजना थी, लेकिन अब समुद्र के रास्ते कच्चा तेल लाने की संभावना पर भी तकनीकी अध्ययन शुरू हो गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश पर सरकारी कंपनियां परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। इसमें गहरे समुद्र में पाइपलाइन बिछाने की तकनीक, लागत और सुरक्षा समेत दूसरे पहलुओं की जांच की जाएगी। भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है। होर्मुज में तनाव के बीच भारत ऊर्जा सप्लाई के लिए वैकल्पिक रास्ते तैयार करना चाहता है।

समुद्र की गहराई सबसे बड़ी चुनौती : इस परियोजना में सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती समुद्र में करीब 3,450 मीटर की गहराई तक पाइपलाइन बिछाना है। इतनी गहराई में पानी का दबाव काफी ज्यादा होता है। पाइपलाइन को सुरक्षित रखना, समुद्र तल की चट्टानों और खाइयों के बीच रास्ता बनाना और भविष्य में इसकी मरम्मत करना भी बड़ी तकनीकी चुनौतियां होंगी।

सीधे सप्लाई से खर्च और जहाजों पर निर्भरता कम होगी : सीधे ओमान, यूएई, कतर और सऊदी अरब के गैस और तेल भंडार से आपूर्ति मिलने पर समुद्री जहाजों पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे तेल और गैस के परिवहन और बीमा पर होने वाला खर्च घट सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अचानक तेल और गैस की कीमत बढ़ने पर भारत पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो सकता है।

3 किमी पाइपलाइन का परीक्षण : परियोजना विकसित करने वाली संस्था साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज ने करीब ?25 करोड़ की लागत से लगभग 3 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर परीक्षण किया है। सभी शर्तें पूरी होने के बाद पूरी परियोजना के निर्माण में करीब 5 से 7 साल लगने का अनुमान है।

मां रेवा पब्लिकेशन एंड प्रिंटर्स
जबलपुर शहर में सबसे कम दामों में
समाचार पत्र के A to Z कार्य का एकमात्र स्थान
प्रिंटिंग
जॉब वर्क
न्यूज पेपर
पीडीएफ
संपर्क करें
7415685293
9589490996
9340553112
68/1 लक्ष्मीपुर विवेकानंद वार्ड, मुस्कान प्लाजा के पीछे, एम आर 4 रोड, उखरी, जबलपुर (मप्र)

सात साल बाद बदली मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान की कमेटी, अब पुराने हिसाब का भी होगा हिसाब?

2019 में खत्म हो चुका था पुरानी कमेटी का कार्यकाल; दुकानों के बकाया किराए, कथित कब्जों, गुमटियों और वक्फ संपत्ति के प्रबंधन पर नई कमेटी के सामने कई सवाल

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। कब्रिस्तान की मिट्टी खामोश होती है। वहां दफ्न लोग सवाल नहीं पूछते। लेकिन जिस जमीन को समाज अपनी अमानत मानता है, उस जमीन का हिसाब जिंदा लोगों को देना पड़ता है। मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान में करीब सात साल बाद नई वक्फ कमेटी का गठन हुआ है। नई कमेटी की जिम्मेदारी मोहम्मद हामिद अंसारी को सौंपी गई है। वकार राजू उपाध्यक्ष, निजाम कुरैशी सचिव और पप्पू कूलर कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। कमेटी नई है। चेहरे नए हैं। उम्मीदें भी नई हैं। लेकिन सवाल आह सवाल तो वही पुराने हैं। और इतने पुराने हैं कि अब उनका जवाब सिर्फ फाइलों से नहीं, हिसाब-किताब से देना होगा। पुरानी कमेटी का कार्यकाल वर्ष 2019 में समाप्त हो गया था। इसके बाद व्यवस्था किस तरह चली, फैसले किस स्तर पर लिए गए, किराया किसने वसूला और कब्रिस्तान की संपत्तियों की निगरानी किसके जिम्मे रही.... इन सवालों पर स्थानीय स्तर पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। अब नई कमेटी बनी है तो पहला सवाल यही है कि क्या सिर्फ पदाधिकारी बदलेंगे या व्यवस्था भी बदलेगी?



दुकानें हैं, लेकिन किराए का हिसाब कहां है?- कब्रिस्तान के मुख्य द्वार से लगी दुकानों को लेकर लंबे समय से सवाल उठाए जाते रहे हैं। स्थानीय सूत्र इन दुकानों से मोहम्मद कादिर, शौकत कुरैशी, मुन्ना मिठाई, शरीफ होटल, जफर और पार्षद परिवार के जुड़े होने की बात बताते हैं। जफर से संबंधित बताई जाने वाली एक दुकान अब खाली हो चुकी है और जानकारी के मुताबिक नई कमेटी वहां अपना कार्यालय बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन बाकी दुकानों का मामला इतना सीधा नहीं दिखाई देता। सूत्रों का दावा है कि कुछ दुकानों का सात-आठ वर्ष तक का किराया बकाया हो सकता है। एक दुकान को लेकर यह दावा और गंभीर है कि उससे लंबे समय से नियमित किराया जमा नहीं हुआ। यह भी कहा जा रहा है कि संबंधित पार्षद परिवार वाली दुकान मूल रूप से अय्यूब शेरा नामक व्यक्ति को किराए पर दी गई थी और बाद में उसका कब्जा दूसरे व्यक्ति के पास चला गया। सूत्रों के अनुसार इसका किराया लगभग 25 साल का पेंडिंग बताया जा रहा है कुछ समय पहले तक यहाँ पार्षद परिवार की साइकिल पंचर बनाने की दुकान थी अब इसे कार्यालय में तब्दील कर दिया गया है।

अगर ऐसा हुआ तो सवाल बेहद सामान्य है।

क्या किरायेदार को वक्फ संपत्ति की दुकान किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपने का अधिकार था?

क्या इसके लिए कमेटी की अनुमति ली गई?

क्या किरायेदारी के रिकॉर्ड में बदलाव हुआ?

और अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो तत्कालीन जिम्मेदार लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की?

इन दावों की आधिकारिक दस्तावेजों से पुष्टि होना अभी जरूरी है। नई कमेटी चाहे तो सबसे पहले दुकानों की मूल आवंटन फाइल, किराया रजिस्टर और जमा रकम का रिकॉर्ड सार्वजनिक कर सकती है।

हिसाब सही है तो किसी को डरने की जरूरत नहीं।

और हिसाब गलत है तो उसे ठीक करने की जरूरत है।

वजूखाना गया, गुमटियां आईं... पैसा कहां जाता है?

कब्रिस्तान के गेट की दूसरी तरफ कभी वजूखाना होने की बात स्थानीय लोग बताते हैं।

आरोप है कि बाद में इस हिस्से में छोटी-छोटी गुमटियां बना दी गईं और फूल बेचने वालों को जगह दे दी गई। स्थानीय स्तर पर प्रति गुमटी करीब एक हजार रुपये किराया लिए जाने की चर्चा है।

मगर सवाल यह नहीं कि एक हजार रुपये ज्यादा हैं या कम।

सवाल है.... वह एक हजार रुपये किसके पास जाता है?

कौन रसीद देता है?

किस खाते में रकम जमा होती है?

किस प्रस्ताव या अनुमति के आधार पर गुमटियां दी गईं? अगर पैसा वक्फ या कब्रिस्तान के खाते में जा रहा है तो उसका रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। और अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो फिर जांच होनी चाहिए कि रकम किसने ली और किस अधिकार से ली। धार्मिक और सार्वजनिक संपत्ति का हिसाब जुबानी नहीं चलता। वहां रसीद, रजिस्टर और बैंक रिकॉर्ड होना चाहिए।



कब्रिस्तान की दीवार और ईंट-रेत-गिट्टी का कारोबार – एक और शिकायत कब्रिस्तान की रब्बानी दरबार के आगे दीवार से लगी जगह को लेकर है।

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक यहां ईंट, रेत और गिट्टी का कारोबार किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि निर्माण सामग्री आसपास तक फैली रहती है।

अब नई कमेटी को पता करना होगा कि जिस जमीन पर कारोबार हो रहा है उसका मालिक कौन है।

अगर जमीन वक्फ की है कब्रिस्तान की है तो कारोबार किस अनुमति से हो रहा है?

किराया दिया जा रहा है या नहीं?

कोई अनुबंध है या नहीं?

और यदि अतिक्रमण है तो इतने वर्षों में उसे हटाने की कोशिश क्यों नहीं हुई?

कब्रिस्तान की जमीन कोई मामूली खाली प्लॉट नहीं होती। उसके साथ लोगों की धार्मिक भावनाएं और उनके पुरखों की यादें जुड़ी होती हैं।

इसलिए जमीन के एक-एक हिस्से का रिकॉर्ड होना चाहिए।

गेट नंबर-1 वीरा गेट के आसपास भी कई शिकायतें- गेट नंबर-1 के आसपास भी कब्जे और कारोबारी गतिविधियों को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं।

कहीं बिरयानी के कारोबार की चर्चा है, कहीं दुकाननुमा ढांचे दिखाई देने की बात कही जाती है यहाँ कब्जा करने वालों के बारे में कहा जा रहा की की वह खुद तो कब्जा किया ही है साथ ही दूसरों को कब्जा करवा उनसे कि किराया भी वसूलते है कई लोगो से किराया लिए जाने के आरोप हैं। कुछ स्थानों पर तो इतना कबाड़ रखा है की सड़क पूरी जाम हो रही है। इनमें से कौन-सी शिकायत सही है और कौन-सी गलत, इसका फैसला अफवाह से नहीं होना चाहिए। नई कमेटी को जमीन के राजस्व और वक्फ रिकॉर्ड के साथ मौके का सीमांकन कराना चाहिए।

फिर लोगों को बताया जाए....

यह जमीन किसकी है?

कौन वैध किरायेदार है?

किसे किस दर पर जगह दी गई?

किसका किराया बाकी है?

और कौन बिना अधिकार बैठा है? किसने कितना कब्जा किया है?

इतना कर दिया जाए तो आधे विवाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। सात साल बाद कमेटी बनी है, इसलिए सात साल का हिसाब भी देखा जाना चाहिए नई कमेटी के सामने सिर्फ कब्रिस्तान की सफाई कराने या दीवार पुतवाने की जिम्मेदारी नहीं है। उसके सामने भरोसा बहाल करने की जिम्मेदारी है। इसके लिए दुकानों का किराया रजिस्टर जांचा जा सकता है। पुराने बकाये की सूची तैयार की जा सकती है। दुकानों और गुमटियों के आवंटन संबंधी दस्तावेज देखे जा सकते हैं। जमीन का सीमांकन कराया जा सकता है और प्रत्येक किरायेदार को विधिवत रसीद देने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। आमदनी कितनी हुई और खर्च कितना हुआ.... इसका सालाना ब्यौरा भी सार्वजनिक किया जा सकता है। पारदर्शिता मुश्किल काम नहीं है। बस हिसाब लिखना पड़ता है।

नई कमेटी को मुबारकबाद, सहयोग का भी भरोसा

मंडी मदार टेकरी वक्फ कब्रिस्तान कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष मोहम्मद हामिद अंसारी को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने मुबारकबाद देते हुए बेहतर कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता रिजवान अंसारी, अंजुमन वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष अनवर अन्नू, मोमिन ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष राशिद अंसारी और रवीन्द्रनाथ टैगोर वार्ड के चर्चित और धाकड़ कांग्रेस नेता आबिद मंसूरी ने मोहम्मद हामिद अंसारी को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई कमेटी कब्रिस्तान की व्यवस्था, साफ-सफाई, वक्फ संपत्तियों की देखरेख और पारदर्शी प्रबंधन की दिशा में बेहतर काम करेगी। वहीं, कब्रिस्तान एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद वसीम ने भी नई कमेटी से बेहतर व्यवस्था की उम्मीद जताते हुए सहयोग का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान के हित में नई कमेटी जो भी जायज और सकारात्मक कदम उठाएगी, उसमें उनकी कमेटी पूरा सहयोग करेगी। नई कमेटी को मिली ये शुभकामनाएं अपने साथ उम्मीदें भी लेकर आई हैं। लेकिन मुबारकबाद के साथ जिम्मेदारी भी आती है। क्योंकि सात साल बाद कमेटी बदली है। अब लोगों की निगाह इस बात पर होगी कि क्या किराए का हिसाब बदलेगा, कब्जों पर रवैया बदलेगा और आमदनी-खर्च का रिकॉर्ड भी साफ दिखाई देगा। कब्रिस्तान में पुराने लोग दफ्न हैं। पुराने सवाल नहीं। अब देखना यह है कि नई कमेटी उन सवालों का जवाब तलाशती है या वे भी फाइलों और खामोशी के नीचे दबे रह जाते हैं।

मुहम्मद अनवार बाबू

तेज और गोली जैसी आवाज वाले हॉर्न से शहर की सड़कों पर बढ़ी परेशानी





दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। शहर की सड़कों पर दोपहिया वाहनों में लगाए जा रहे तेज आवाज और अजीब किस्म के हॉर्न आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। कई बाइक सवार सामान्य हॉर्न की जगह तेज, कर्कश और अलग-अलग धुन वाले हॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं। अचानक बजने वाली इन तेज आवाजों से राहगीरों, बुजुर्गों, बच्चों और वाहन चालकों को असहजता का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ बाइक सवार अपने वाहनों में ऐसे हॉर्न लगवा रहे हैं, जिनसे गोली चलने जैसी आवाज निकलती है। अचानक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई देने से आसपास मौजूद लोग कई बार घबरा जाते हैं। मुख्य सड़कों के अलावा गलियों और आवासीय क्षेत्रों में भी इस तरह के हॉर्न का इस्तेमाल किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। व्यस्त बाजारों, आवासीय क्षेत्रों और स्कूल-कॉलेजों के आसपास ऐसे हॉर्न अधिक परेशानी पैदा कर रहे हैं। कई बार बाइक सवार बिना आवश्यकता लगातार हॉर्न बजाते हुए निकल जाते हैं। तेज आवाज के कारण सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालक अचानक चौंक जाते हैं, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ने और दुर्घटना की आशंका बढ़ सकती है। अस्पतालों और अन्य शांत क्षेत्रों में भी तेज और कर्कश हॉर्न को लेकर लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वाहनों में निर्धारित मानक के हॉर्न का ही उपयोग होना चाहिए। अनावश्यक रूप से तेज आवाज करने वाले हॉर्न न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं, बल्कि सड़क पर दूसरे लोगों के लिए असुविधा और परेशानी भी पैदा करते हैं। नागरिकों के अनुसार यातायात नियमों के पालन के साथ वाहनों में लगाए गए हॉर्न की भी नियमित जांच की जानी चाहिए। लोगों का कहना है कि कई वाहन चालक नियमों की अनदेखी कर ऐसे हॉर्न लगवा लेते हैं और लंबे समय तक शहर की सड़कों पर उनका इस्तेमाल करते रहते हैं। नियमित जांच से ऐसे मामलों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई लगातार नहीं होने के कारण ऐसे वाहन चालकों के हौसले बने हुए हैं। कभी-कभार कार्रवाई किए जाने के बाद फिर निगरानी कमजोर पड़ जाती है। इसके चलते तेज आवाज वाले हॉर्न लगाए बाइक सवार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खुलेआम घूमते नजर आते हैं। नागरिकों ने यातायात पुलिस से मुख्य मार्गों के साथ बाजार, स्कूल-कॉलेज और आवासीय क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की जांच कर निर्धारित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि सड़क पर अनावश्यक तेज आवाज करने वाले हॉर्न के इस्तेमाल को रोका जा सके। लोगों का कहना है कि सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए केवल वाहन की गति और यातायात नियमों पर ही ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वाहनों में इस्तेमाल होने वाले हॉर्न की आवाज भी नियंत्रित होना जरूरी है। सड़क पर शांति और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना वाहन चालकों के साथ-साथ संबंधित विभागों की भी जिम्मेदारी है।

मेडिकल कॉलेज परिसर में युवक से मारपीट कर स्कूटी और मोबाइल लूटा

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। मेडिकल कॉलेज परिसर में स्कूटी पर बैठे युवक के साथ तीन युवकों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और उसकी स्कूटी व मोबाइल छीनकर फरार हो गए। विरोध करने पर आरोपितों ने युवक को हाथ-मुक्कों से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। घटना में युवक के सिर, हाथ-पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। पीड़ित की शिकायत पर गढ़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गढ़ा पुलिस के अनुसार सिद्धबाबा रोड, हनुमानताल निवासी कमलेश अहिरवार उम्र 48 वर्ष इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। उसने 28 सितंबर को थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। कमलेश ने पुलिस को बताया कि वह 21 सितंबर को दोपहर करीब डेढ़ बजे अपनी एक्सिस स्कूटी क्रमांक एमपी 20 यूए 4003 से मुकुनवारा गया था। कमलेश के अनुसार रात करीब साढ़े 10 बजे वह मेडिकल कॉलेज के गेट के पास पहुंचा और कुछ देर बाद मेडिकल कॉलेज परिसर के अंदर अपनी स्कूटी पर बैठा



था। इसी दौरान एक युवक वहां आया और उसकी एक्सिस स्कूटी को उठाकर ले जाने का प्रयास करने लगा। कमलेश ने युवक को रोकने की कोशिश की। पीड़ित के रोकने पर युवक के दो अन्य साथी भी वहां पहुंच गए। तीनों ने कमलेश के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। कमलेश ने उन्हें गाली देने से मना किया तो तीनों ने उसके साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से वह संभल नहीं सका और आरोपितों ने उसकी स्कूटी छीन ली। आरोपित युवक कमलेश का ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन भी छीनकर ले गए। पीड़ित के अनुसार मोबाइल के कवर में कुछ रुपये भी रखे हुए थे। आरोपितों ने मोबाइल और रुपये लेने के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। मारपीट में कमलेश के सिर, हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। घटना के बाद उसने मामले की जानकारी पुलिस को दी और 28 सितंबर को गढ़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 134, 296(बी), 303(2), 351(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की जांच करने के साथ आरोपितों की पहचान और तलाश में जुटी है। पुलिस मेडिकल कॉलेज परिसर और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों की भी जांच कर सकती है। घटना के दौरान मौजूद लोगों से पूछताछ कर आरोपितों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

किराना दुकान के गोदाम में चावल की बोरियों के पीछे छिपा आठ फीट लंबा सांप

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। शास्त्री नगर स्थित एक किराना दुकान के गोदाम में चावल की बोरियों के पीछे करीब आठ फीट लंबा सांप मिलने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सांप को देखकर कर्मचारियों ने तत्काल दुकान संचालक को इसकी जानकारी दी। इसके बाद सर्प विशेषज्ञ को बुलाया गया, जिन्होंने सांप को सुरक्षित बाहर निकालकर जंगल में छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार सांप किराना दुकान के गोदाम में चूहों का शिकार करने के लिए पहुंचा था। दोपहर के समय दुकान के कर्मचारी गोदाम में रखी चावल की बोरियों को व्यवस्थित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बोरियों को एक तरफ किया तो पीछे छिपा सांप दिखाई दिया। अचानक सांप दिखाई देने से कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। सांप



काफी लंबा होने के कारण कर्मचारी उसके पास जाने से बचते रहे। उन्होंने दुकान संचालक राजू साहू को घटना की जानकारी दी और सांप को सुरक्षित निकालने के लिए सर्प विशेषज्ञ से संपर्क करने को कहा। दुकान संचालक ने तत्काल सर्प मित्र गजेंद्र दुबे को सूचना दी। जानकारी मिलने के बाद गजेंद्र दुबे मौके पर पहुंचे और सावधानीपूर्वक सांप का रेस्क्यू किया। उन्होंने सांप को पकड़ने के बाद उसे सुरक्षित तरीके से दुकान से बाहर निकाला। रेस्क्यू के दौरान सांप को किसी तरह की चोट नहीं पहुंची। सर्प मित्र ने उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। सांप के दुकान से बाहर निकलने के बाद कर्मचारियों और दुकान संचालक ने राहत की सांस ली।

बाइक सवार बदमाश युवक का मोबाइल झपटकर फरार

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। अधारताल थाना क्षेत्र के शोभापुर में किराना सामान लेने जा रहे युवक से बाइक सवार दो युवक मोबाइल झपटकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गनपत उर्फ लकी गौड़ निवासी ग्राम अतरिया, थाना गोसलपुर, वर्तमान में शोभापुर ब्रिज के पास गोवर्धन इंडस्ट्रीज की प्लास्टिक फैक्ट्री में मशीन चलाता है। 28 सितंबर की शाम करीब सात बजे वह फैक्ट्री से पैदल किराना दुकान की ओर जा रहा था। इस दौरान वह मोबाइल पर बात कर रहा था। तभी पीछे से बाइक पर सवार दो युवक उसके पास पहुंचे। बाइक पर पीछे बैठे युवक ने अचानक झपट्टा मारकर उसके हाथ से पोको कंपनी का मोबाइल छीन लिया। वारदात के बाद दोनों युवक बाइक से तेजी से फरार हो गए। अचानक हुई घटना से युवक कुछ समझ पाता, इससे पहले ही आरोपित उसकी पहुंच से दूर निकल चुके थे। पीड़ित ने आसपास उनकी तलाश की, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चला। इसके बाद उसने अधारताल थाने पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी।

जीआरपी की कार्रवाई में मोबाइल चोरी की तीन वारदातों का खुलासा

ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बनाया निशाना चोरी के मोबाइल सहित आरोपी गिरफ्तार

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल चोरी करने वाले एक आरोपी को जीआरपी जबलपुर ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी से मोबाइल चोरी की तीन अलग अलग घटनाओं का खुलासा हुआ है। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। आरोपी की पहचान दीपक लीलानी उर्फ देव उर्फ दाऊ उम्र 20 वर्ष निवासी आचार्य कृपलानी वार्ड कैरिन लाइन माधवनगर कटनी के रूप में हुई है। जीआरपी के अनुसार 29 सितंबर 2026 को प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने करीब एक माह पूर्व जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर गोंडवाना एक्सप्रेस में भीड़ का फायदा उठाकर एक यात्री की जेब से रियलमी कंपनी का मोबाइल चोरी करना स्वीकार किया। चोरी किए गए मोबाइल की कीमत करीब 28 हजार रुपये बताई गई है। इस मामले में थाना जीआरपी जबलपुर में अपराध क्रमांक 633 26 धारा 303 2 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज है। पुलिस ने साक्ष्य संकलित करने के बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया।

पूछताछ में सामने आई दूसरी वारदात- पुलिस पूछताछ में आरोपी ने एक अन्य वारदात का भी खुलासा किया। आरोपी के मुताबिक करीब छह से सात दिन पहले रेलवे स्टेशन सिहोरा में उसने सो रहे एक यात्री की जेब से मोटोरोला कंपनी का मोबाइल चोरी किया था। चोरी किए गए मोबाइल की कीमत करीब 17 हजार 300 रुपये बताई गई है। आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने मोबाइल बरामद कर लिया और मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू की।

रीवा शटल में दोस्ती बढ़ाकर मोबाइल चोरी और फिर 20 हजार रुपये का ट्रांजेक्शन- पूछताछ के दौरान आरोपी से तीसरी



वारदात की जानकारी भी सामने आई। पुलिस के अनुसार रीवा शटल ट्रेन में आरोपी ने एक यात्री से बातचीत के दौरान दोस्ती बढ़ाई और इसी दौरान उसका मोबाइल चोरी कर लिया। इसके बाद आरोपी आधारताल स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया। पुलिस के अनुसार चोरी किए गए मोबाइल के माध्यम से आरोपी ने यूपीआई के जरिए करीब 20 हजार रुपये का ट्रांजेक्शन भी किया। इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत विवेचना की जा रही है।

आपराधिक रिकॉर्ड की जांच- जीआरपी द्वारा आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पुलिस अब चोरी की अन्य घटनाओं में आरोपी की संभावित संलिप्तता और बरामद मोबाइलों के संबंध में भी जांच कर रही है।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई- यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर श्री सुंदर सिंह कनेश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेल श्री आशुतोष मिश्रा एवं उप पुलिस अधीक्षक रेल श्री विजय गुठरिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी संजीवनी राजपूत के नेतृत्व में की गई। पूरी कार्रवाई में प्रधान आरक्षक मनोज मिश्रा प्रधान आरक्षक अरुण तिवारी प्रधान आरक्षक परशुराम प्रधान आरक्षक रविकांत रजक प्रधान आरक्षक 122 ओम प्रकाश बघेल प्रधान आरक्षक गोपाल प्रधान आरक्षक उमेश तथा प्रधान आरक्षक सागर उपाध्याय की विशेष भूमिका रही।

यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी- जीआरपी जबलपुर द्वारा रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में यात्रियों के साथ होने वाली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी और संदिग्धों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए चोरी और अन्य अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

रिपोर्टर
मोहम्मद अकरम अंसारी

पुराने तहसील कार्यालय से 24 ईवीएम मशीन हुई चोरी, शिकायत जे बाद मामला हुआ दर्ज, पुलिस जांच में जुटी



दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। जिला मुख्यालय के पुराने तहसील कार्यालय के पीछे बने ईवीएम वेयरहाउस में सुरक्षित रखी गई ईवीएम मशीनों में से 24 मशीनें गायब मिलने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है। मामले में 30 सितम्बर को प्राथमिक विद्यालय सीतापुर के सहायक शिक्षक फूल सिंह पिता धना सिंह निवासी कराटोला ने तहसीलदार अनूपपुर वेद प्रकाश सिंह तथा प्राथमिक विद्यालय बस्ती के सहायक शिक्षक संजय निगम के साथ कोतवाली पहुंच शिकायत दर्ज कराई। जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 331(4) और 305(ए) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है। मामला उस समय सामने आया, जब पुराने तहसील भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण उसे डिसमेंटल कराया जा रहा था। इस दौरान ईवीएम मशीनों को पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में संचालित तहसील कार्यालय के कक्ष पर स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान संबंधित पुराने तहसील कार्यालय भवन के पीछे बने ईव्हीएम वेयर हाउस भवन की दीवार क्षतिग्रस्त मिली। इसके बाद मशीनों का भौतिक सत्यापन कराया गया तो रिकॉर्ड और मौके पर उपलब्ध मशीनों की संख्या में अंतर सामने आया। शिकायत के अनुसार भौतिक सत्यापन के दौरान कुल 24 ईवीएम मशीनें कम पाई गईं। इनमें 8 बैलेट यूनिट (बीयू) और 16 कंट्रोल यूनिट (सीयू) शामिल हैं। मशीनों के सीरियल नंबर भी शिकायत में दर्ज किए गए हैं। शिकायत में बताया गया है कि वर्ष 2014 में स्थानीय निर्वाचन यानी पंचायत चुनाव के लिए अनूपपुर के पुराने तहसील कार्यालय में बड़ी संख्या में ईवीएम मशीनें सुरक्षित रखी गई थीं। रिकॉर्ड के मुताबिक वहां 620 कंट्रोल यूनिट और 1670 बैलेट यूनिट रखी गई थीं। कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि 24 ईवीएम मशीनें वास्तव में कब गायब हुईं, क्या इन्हें चोरी कर बाहर ले जाया गया या रिकॉर्ड और भौतिक उपलब्धता के बीच किसी अन्य कारण से अंतर आया। फिलहाल 24 ईवीएम मशीनों के गायब होने और पुराने क्षतिग्रस्त तहसील भवन अनूपपुर के डिसमेंटल किये जाने के कार्य आदेश के बाद भी ईव्हीएम वेयर हाउस से ईव्हीएम को पहले क्यो नही हटाया गया।



यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई, 78 हजार 600 रुपये का जुमार्ना

दैनिक रेवांचल टाइम्स शहडोल। जिले में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चल रहे इस अभियान के तहत यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। यातायात प्रभारी अमित विश्वकर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, शराब के नशे में वाहन चलाने तथा बिना बीमा के वाहन चलाने सहित अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई की जा रही है। 28 से 30 सितंबर तक तीन दिनों में बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले 73 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 21 हजार 900 रुपये समन शुल्क वसूला गया। इसी प्रकार चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वाले 35 वाहन चालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त ओवरलोड वाहन, नशे में वाहन चलाने तथा बिना बीमा के वाहन चलाने के मामलों में भी कार्रवाई की गई। तीन दिनों में विभिन्न यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से कुल 78 हजार 600 रुपये समन शुल्क वसूला गया।

दहेज प्रताड़ना से नवविवाहिता ने की थी फांसी लगाकर आत्महत्या आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार



दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। थाना अंतर्गत करीब 14 दिन पूर्व नवविवाहिता महिला की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को दहेज प्रताड़ना से हुई मौत के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामला नगर के वार्ड क्रमांक 12 स्थित गोविंद कॉलरी का है जानकारी के अनुसार 17 सितंबर को 20 वर्षीय नवविवाहिता नेहा चौहान का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया था। घटना के बाद मायके पक्ष ने उसके पति पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट एवं प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए थेकानून प्रवर्तन बताया गया कि मृतिका नेहा ने करीब छह माह पूर्व पवन चौहान के साथ प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद दोनों आमाडांड कॉलोनी में परिवार के साथ रह रहे थे। मायके पक्ष का आरोप था कि पति द्वारा आए दिन विवाद करते हुए नेहा के साथ मारपीट की जाती थी और दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था। इस संबंध में थाने में शिकायत किए जाने की बात भी सामने आई थी मामला नवविवाहिता की मौत से जुड़ा होने के कारण एसडीओपी आरती शाक्य के निर्देशन में पुलिस ने मामले की गंभीरता से विवेचना की। पुलिस ने मृतिका की मां, पिता, भाई सहित मायके पक्ष के अन्य लोगों के बयान दर्ज किए। विवेचना के दौरान मृतिका के पति द्वारा आए दिन विवाद एवं मारपीट कर प्रताड़ित किए जाने की जानकारी सामने आने पर पुलिस ने आरोपी पति पवन चौहान के विरुद्ध बीएनएस की धारा 108 एवं 85 के तहत प्रकरण दर्ज किया।

अस्पताल में नही मिला एम्बुलेंस, चार घंटे तड़पती रही महिला, शिफ्ट करते समय हुई मौत, लापरवाही का लगा आरोप

दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। डॉक्टरों की कमी और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवालों के घेरे में रहने वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा एक बार फिर सुर्खियों में है। रविवार को उपचार के लिए भर्ती 60 वर्षीय महिला को चिकित्सकों ने गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया, लेकिन परिजनों के अनुसार एंबुलेंस के इंतजार में महिला करीब चार घंटे तक अस्पताल में दर्द से तड़पती रही। देर शाम एंबुलेंस पहुंचने के बाद महिला को हायर सेंटर ले जाने के लिए शिफ्ट किया जा रहा था, तभी उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार देवरी निवासी शांतिबाई केवट उम्र 60 वर्ष को रविवार सुबह शुगर एवं सांस संबंधी परेशानी के चलते उनकी पुत्री मोना केवट और दामाद राजू केवट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा लेकर पहुंचे थे। यहां उपचार के दौरान



दोपहर करीब 1 बजे चिकित्सकों ने महिला की हालत गंभीर बताते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। मृतका की पुत्री मोना केवट के अनुसार रेफर किए जाने के बाद दोपहर करीब 2 बजे से परिजन एंबुलेंस का इंतजार करते रहे। इस दौरान महिला की हालत बिगड़ती रही और वह दर्द से कराहती रही। बेबस पुत्री इधर उधर फोन लगाकर मदद की गुहार लगाती रही। परिजनों एवं स्थानीय लोगों द्वारा एंबुलेंस के लिए बीएमओ एवं सीएमओ को भी सूचना दी गई, इसके बावजूद करीब चार घंटे तक एंबुलेंस नहीं पहुंची परिजनों के मुताबिक शाम करीब 6 बजे के बाद एंबुलेंस अस्पताल पहुंची। महिला को हायर सेंटर ले जाने के लिए जैसे ही शिफ्ट किया जा रहा था, उसी दौरान उसकी सांस उखड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद अस्पताल परिसर में परिजनों की चीख पुकार मच गई। दामाद राजू केवट ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच कर दोषी पर कार्यवाही की मांग की है गई है बीएमओ डॉ के एल दीवान के अनुसार एंबुलेंस उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए जो देर से पहुंची। जिस कारण मरीज को परेशानी हैं।

सोनू कोल हत्याकांड में दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा, धारदार हथियार से की थी हत्या

दैनिक रेवांचल टाइम्स उमरिया। वर्ष 2020 में सामने आए सोनू कोल हत्याकांड में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रियदर्शन शर्मा की अदालत ने नौरोजाबाद निवासी जावेद मुस्लिम और राजेश यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी माना। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत जानकारी के मुताबिक घटना 1 अप्रैल 2020 की रात की है। कोरोना संक्रमण के दौरान सोनू कोल जिला जेल से रिहा होकर घर आया था। घटना वाली रात वह अपने साथी विकास वर्मन के साथ बाजारपुरा, नौरोजाबाद से सामान लेकर लौट रहा था। बताया गया कि रात करीब 8 बजे दोनों बड़े ग्राउंड के पीछे पानी टंकी नर्सरी के पास पहुंचे, जहां आरोपियों ने सोनू को रोक लिया। इसी दौरान पुराने विवाद को लेकर सोनू के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। आरोप है कि जावेद ने धारदार हथियार से हमला किया,



जबकि राजेश ने सोनू को पकड़ लिया। हमले में सोनू के गले और कमर के पीछे गंभीर चोटें आईं। घायल सोनू के शरीर से अधिक रक्तस्राव होने लगा। शोर सुनकर उसके साथ मौजूद विकास वर्मन ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद सोनू वहां से निकलकर नौरोजाबाद थाने पहुंचा। पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 87/2020 दर्ज कर धारा 341, 294, 307, 34 भादंसं सहित एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं में प्रकरण कायम किया था। बाद में उपचार के दौरान सोनू कोल की मृत्यु होने पर मामले में हत्या की धारा 302 भी जोड़ी गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने प्रत्यक्षदर्शी विकास वर्मन सहित अन्य साक्ष्यों और मृतक के मृत्यु पूर्व कथन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन के तर्कों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने जावेद मुस्लिम और राजेश यादव को हत्या का दोषी मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया।

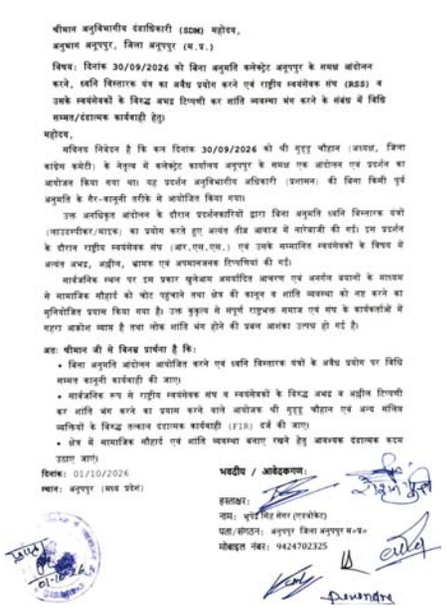


रेलवे लाइन पार करते समय महिला आई रेलगाड़ी की चपेट में, हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी

दैनिक रेवांचल टाइम्स शहडोल। अमलाई थाना क्षेत्र के टिकुरी टोला के पास रेलवे लाइन पार करते समय एक बुजुर्ग महिला मालगाड़ी की चपेट में आ गई। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला को कम सुनाई देता था, जिसके कारण वह ट्रेन का हॉर्न नहीं सुन सकी। घटना की सूचना रेलवेकर्मियों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अमलाई थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर चार निवासी सावित्री केवट (65) घर के पास स्थित टिकुरी टोला के समीप रेलवे लाइन पार कर शौच के लिए गई थीं। शौच के बाद वह रेलवे लाइन पार कर वापस घर लौट रही थीं। इसी दौरान तीसरी लाइन पर मालगाड़ी आ गई। ट्रेन के चालक ने महिला को पटरी पर देखकर लंबा हॉर्न बजाया लेकिन कम सुनाई देने के कारण महिला को इसकी आवाज नहीं सुनाई दी और वे मालगाड़ी की चपेट में आ गईं। हादसे की जानकारी मिलते ही अमलाई पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या महिला के घर में शौचालय था। सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर-घर शौचालय निर्माण और खुले में शौच से मुक्ति के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की गई हैं। यदि महिला के घर में शौचालय उपलब्ध था तो वह शौच के लिए रेलवे लाइन के पास क्यों गईं वहीं यदि शौचालय नहीं था तो सरकारी योजना के तहत उनके घर में शौचालय क्यों नहीं बन पाया, यह भी जांच का विषय है।

बिना अनुमति प्रदर्शन व आपत्तिजनक नारे लगाने की शिकायत, अधिवक्ता ने एसडीएम से कार्रवाई की मांग

दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। जिला मुख्यालय अनूपपुर में कांग्रेस द्वारा बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन और रैली निकालने तथा कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने को लेकर विवाद सामने आया है। मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेन्द्र सिंह सेंगर ने एसडीएम अनूपपुर को ज्ञापन सौंपकर संबंधित लोगों के विरुद्ध विधिसंगत कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता भूपेन्द्र सिंह सेंगर द्वारा दिए गए ज्ञापन के अनुसार, कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकताओं द्वारा जिला मुख्यालय में रैली निकाली गई और कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध आपत्तिजनक एवं भड़काऊ नारे लगाए गए। ज्ञापन में कहा गया है कि इस प्रकार के नारों से



भीमान अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) महोदय,
अनुभाग अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

विषय: दिनांक 30/09/2026 को बिना अनुमति कलेक्ट्रेट अनूपपुर के समक्ष आयोजन करने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का अवैध प्रयोग करने एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) व उसके स्वयंसेवकों के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी कर शांति व्यवस्था भंग करने के संबंध में विधि सम्मत/दंडात्मक कार्यवाही हेतु।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि कल दिनांक 30/09/2026 को भी गुरुद्वारा चौहान (अपर, जिला कांग्रेस कमेटी) के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय अनूपपुर के समक्ष एक आंदोलन एवं प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। यह प्रदर्शन अनुविभागीय अधिकारी (उमरिया) की बिना किसी पूर्व अनुमति के गैर-कानूनी तरीके से आयोजित किया गया।

उक्त अनधिकृत आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों (माइकसीपीकर/भाटक) का प्रयोग करते हुए अत्यंत तीव्र आवाज में नारेबाजी की गई। इस प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) एवं उसके सम्मानित स्वयंसेवकों के विषय में अभद्र अभद्र, अशोभन, भ्रामक एवं अपमानजनक टिप्पणियां की गईं।

सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार सूचीबद्ध अमर्यादित आचरण एवं अनर्गल प्रचारों के माध्यम से सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाने तथा क्षेत्र की कानून व शांति व्यवस्था को नए करने का सुनियोजित प्रयास किया गया है। उक्त कृत्यों से संपूर्ण राष्ट्रभक्त समाज एवं संघ के कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश व्याप्त है तथा लोक शांति भंग होने की प्रबल आशंका उत्पन्न हो गई है।

अतः भीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि:

- बिना अनुमति आंदोलन आयोजित करने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अवैध प्रयोग पर विधि सम्मत कानूनी कार्यवाही की जाए।
- सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व स्वयंसेवकों के विरुद्ध अभद्र व अशोभन टिप्पणी कर शांति भंग करने का प्रयास करने वाले आयोजक की गुरुद्वारा चौहान एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही (FIR) दर्ज की जाए।
- क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दंडात्मक कदम उठाए जाएं।

दिनांक: 01/10/2026
स्थान: अनूपपुर (मध्य प्रदेश)

भवदीय / आवेदकगण:
हस्ताक्षर:
नाम: भूपेंद्र सिंह सेंगर (एडवोकेट)
पता/कांटक्ट: अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र.
मोबाइल नंबर: 9424702325

सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका है। शिकायतकर्ता ने प्रदर्शन के लिए अनुमति लिए जाने तथा कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश से संबंधित नियमों की भी जांच किए जाने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया है। मामले को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष हीरा सिंह श्याम सहित अन्य लोगों द्वारा भी आपत्ति जताए जाने की बात सामने आई है। भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान लगाए गए नारों पर नाराजगी व्यक्त की है। अधिवक्ता सेंगर ने एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में पूरे घटनाक्रम की जांच कर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की है। अब प्रशासन द्वारा शिकायत पर क्या कदम उठाया जाता है, इस पर लोगों की नजर बनी हुई है।

पीआरटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग परीक्षा में विद्यार्थियों उत्कृष्ट प्रदर्शन, 100% परीक्षा परिणाम

दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। पीआरटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अनूपपुर के विद्यार्थियों ने एक बार फिर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम हासिल कर महाविद्यालय एवं जिले का नाम रोशन किया है। मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा देर रात घोषित बी.एससी. नर्सिंग द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में महाविद्यालय का परिणाम 100 प्रतिशत रहा। बी.एससी. नर्सिंग तृतीय वर्ष (सत्र 2020-21) में बसंती देवी ने 83 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। निशी पनारिया ने 82 प्रतिशत के साथ द्वितीय तथा ज्योति सिंह ने 81 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान हासिल किया। इसी प्रकार बी.एससी. नर्सिंग द्वितीय वर्ष (सत्र 2022-23) में स्वाति साहू ने 80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। लक्ष्मी केवट एवं रिया वर्मा ने 78-78 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। महाविद्यालय के शानदार परीक्षा परिणाम पर संचालक डॉ. देवेंद्र कुमार तिवारी ने सभी सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को बधाई देते हुए विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप महाविद्यालय ने यह उपलब्धि हासिल की है।

संपादकीय

फॉर्म 6 का फ्रॉड

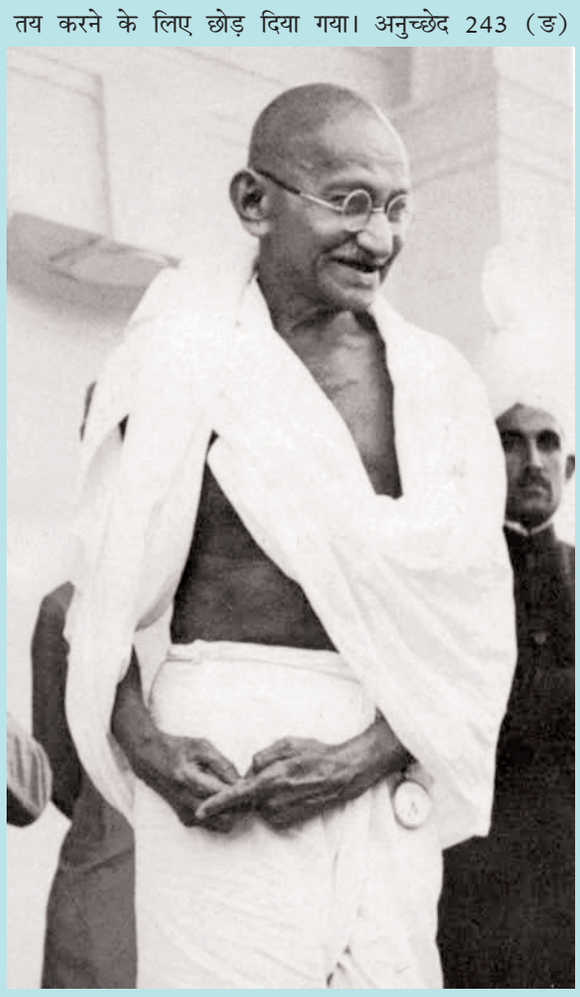
चुनाव आयोग, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार गुप्ता, विपक्षी आंदोलन और राजनीति के निशाने पर हैं। कांग्रेस कार्यसमिति और शेष विपक्ष की सामूहिक मांग है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को निलंबित किया जाए। यदि संभव है, तो उसे रद्द ही कर दिया जाए। अभी तक जिन 13.37 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उन्हें बहाल किया जाए। यह कैसे संभव है, क्योंकि उनमें से 2.80 करोड़ से ज्यादा मतदाता तो दिवंगत (मृत) हो चुके हैं। शेष 10.57 करोड़ काटे गए नामों पर चुनाव आयोग को बाध्य किया जाना चाहिए। दिल्ली में यह मामला सामने आया है। बेला एस्टेट में अधिकतर झुग्गी-झोंपडि?ां थीं। लोगों ने अवैध अतिक्रमण किए हुए थे और वे वहां बसे हुए थे। 2022-23 में उन झुग्गियों को तोड़ दिया गया। वहां 728 वैध मतदाता रहते थे, जिनके पास चुनाव आयोग की मान्यता थी और वे लगातार मतदान करते रहे थे। झुग्गियां टूटीं, तो वे बेघर हो गए। एसआईआर अभियान के तहत बीएलओ को उस जगह कोई नहीं मिला। किसी एक ने मतदाता पहचान पत्र दिखाया। नतीजतन 728 में से 727 मतदाताओं के नाम काट दिए गए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन बेघरों के पास गए और मोबाइल पर ईआरओ से पूछा कि इतने नाम किस आधार पर काट दिए गए? बहरहाल जब यह खबर टीवी चैनलों और अखबारों की सुर्खियों में आ गई कि बेला एस्टेट के बेघर परिवार फ्लाईओवर के नीचे जीने को विवश हैं, तो चुनाव आयोग ने अपने बीएलओ भी वहां भेजे। कटे हुए नामों के उन लोगों को फॉर्म 6 भर कर नया मतदाता बनने की सलाह दी गई। खबर बताई जाती है कि 418 लोगों से फॉर्म 6 भरवा भी लिए गए हैं। अब नई मतदाता-सूची में उनके नाम भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने यह संवैधानिक फ्रॉड खेला है। फॉर्म 6 उन लोगों के लिए है, जो बिल्कुल पहली बार मतदाता बनना चाहते हैं। वे पहले कभी भी मतदाता न रहे हों। ऐसा घोषणा-पत्र भी भर कर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। लेकिन ये तो पहले भी मतदाता रहे हैं और उन्होंने एसआईआर में अधिकृत फॉर्म भी भरा था। क्या यह संवैधानिक कवायद है? यदि 418 काटे गए नाम, अंततः, मतदाता बन जाते हैं, तो शेष लोग भी मतदाता बनाए जा सकते हैं। तो फिर एसआईआर का औचित्य क्या रहा? क्या इस तरह चुनाव आयोग फ्रॉड नहीं कर रहा है और फॉर्म 6 के साथ झूठे घोषणा पत्र भी नहीं भरवा रहा है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जानकारी में यह पूरा मामला है, लिहाजा उनका आंदोलन सीईसी ज्ञानेश कुमार गुप्ता के इस्तीफे पर केंद्रित है। राहुल को यकीन है कि अंततः प्रधानमंत्री मोदी ही सीईसी का इस्तीफा करवाएंगे, क्योंकि ज्ञानेश तो उन्हीं की कठपुतली हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने तो प्रधानमंत्री का ही इस्तीफा मांग लिया है। फॉर्म 6 के इस कथित फजीर्वाड़े में भाजपा के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी फंसे हैं। वह जब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो वह पंजाब के मतदाता थे और आप के प्रत्याशी थे, लेकिन बाद में आप के 7 राज्यसभा सांसद पालाबदल कर भाजपा में शामिल हो गए, तो अब उन्हें दिल्ली का मतदाता बनाया गया है। इसमें कोई अपराध नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्थानांतरित होता है, तो मतदाता भी बदला जा सकता है। अलबत्ता संवैधानिक हेराफेरी न की जाए। बताया जाता है कि राघव चड्ढा से फॉर्म 6 भरवाया गया है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन आप ऐसा कह रही है और अदालत में इसे चुनौती देने की बात भी पार्टी ने की है। दरअसल एसआईआर का मुद्दा बेहद पेचीदा हो गया है। दिल्ली में ही 9 लाख से अधिक बांग्लादेशी बस चुके हैं। वे अभी तक मतदाता भी बने रहे हैं। सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने उन्हें एसआईआर के दौरान क्या चिह्नित किया है? सर्वोच्च अदालत में यह मामला विचाराधीन है और एक मामले में तो एसआईआर को अवैध करार देने की भी मांग की गई है। जो भी हश्र होगा, देखा जाएगा, लेकिन इस मुद्दे ने हमारी राजनीति को बिल्कुल विभाजित और विषाक्त बना दिया है। विपक्ष को चुनाव आयोग की मनमानियां पसंद नहीं हैं और सारा देश इस मसले पर आंदोलित है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लेकर आ रहा है। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के जरिए हटाना आसान नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास वांछित बहुमत नहीं है, फिर भी इसके जरिए चुनाव आयोग के खिलाफ एक तरह का माहौल तो बन ही रहा है।

गांधी जयंती विशेष

गांधी के गांव गणराज्य का सपना आज भी अधुरा

दैनिक रेवांचल टाईम्स अगस्त 1947 को देश की पहली स्वतंत्रता दिवस पर गांधीजी ने कहा था 'मेरे सपनों का भारत सात लाख गांव गणराज्यों का संघ' होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत से यह उम्मीद की गई थी कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्तता की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। इस संवैधानिक निर्देश के पालन में केन्द्र और राज्य सरकार विफल रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में आदिवासी वयवस्था के लिए पंचशील निर्धारित किये। इनमें बिना बाहरी हस्तक्षेप के समाज द्वारा अपनी परम्परा के अनुसार अपनी व्यवस्था करने का अधिकार मुख्य बिन्दु था। 1956 में बलवंत राय समिति ने देश में तीन स्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिये सिफारिश की थी। उसी के अनुसार जिला, विकास खंड और गांव स्तर पर पंचायतों का गठन हुआ।

इस व्यवस्था में ग्राम सभा की भूमिका पर ध्यान नहीं दिया गया।इस समिति की यह मान्यता थी कि गांव समाज अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है।इसके लिए फिर से 1978 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति के समक्ष भारत सरकार की ओर से गृह मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव डॉक्टर ब्रह्म देव शर्मा ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा के रूप में गांव समाज को अपनी पूरी व्यवस्था करने के लिए अधिकार देने का प्रस्ताव किया। परन्तु समिति ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।उसके अनुसार ग्राम सभा को कुछ जिम्मेदारियां दी जा सकती है, अधिकार नहीं।ग्राम सभा पंचायत राज व्यवस्था की आधारशिला होना चाहिए। इसके बिना प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण तो अर्थहीन रहेगा ही वरन- स्वयं लोकतंत्र कमजोर होकर टूट सकता है।अनुसूचित क्षेत्रों के लिए सामान्य पंचायत व्यवस्था असंगत था। संविधान में पंचायत राज के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए 1988 में राजीव गाँधी के नेतृत्व में संविधान संशोधन प्रस्तावित हुआ। इस विधेयक में अनुसूचित क्षेत्रों को पंचायत राज की सामान्य व्यवस्था से बाहर रखा गया था। उसमें सबंधित राज्यपालों से उम्मीद की गई थी कि वे अपने - अपने राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था करेंगे।परन्तु इस विधेयक को संसद की मंजूरी नहीं मिल पाई।1990 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त डॉक्टर ब्रह्म देव शर्मा ने राष्ट्रपति को 29 वीं रिपोर्ट दिया।इस रिपोर्ट को संसद में बहस के लिए भी रखा गया परन्तु रिपोर्ट पर चर्चा नहीं कराया गया।संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत आयुक्त ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा अंग्रेजी राज्य की उस कानून व्यवस्था को संविधान की भावना और नैसर्गिक न्याय के खिलाफ बताया, जिसके कारण वो वह जन्मजात अपराधी हो गया और उसके जिंदगी के बुनियादी अधिकार की कदम - कदम पर अवमानना होती रही है। इसमें शिफारिश की गई कि कम से कम आदिवासी इलाकों में पूरी तरह स्वशासी व्यवस्था की जाए जिसमें स्थानीय समाज को अपना जीवन चलाने और पूरे संसाधनों के रखरखाव और उपयोग का असंदिग्ध रूप से पूरा अधिकार हो। यही गांव गणराज्य का सार तत्व है।1993 में पंचायत व्यवस्था की स्थापना के लिए भारत के संविधान में 73 वां संशोधन कर भाग 9 को जोड़ा गया। इस संशोधन के अनुसार संविधान में 'ग्राम सभा' की प्रतिष्ठा तो हुई परन्तु उसके कर्तव्य और शक्तियों को राज्य विधान मंडलों द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया गया। अनुच्छेद 243 (ङ)



?उपभाग(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों को इस व्यवस्था से अलग रखा गया।परन्तु उसी अनुच्छेद के उपभाग(4) में संसद को यह अधिकार सौपा गया कि उस भाग के प्रावधानों में जरुरी फेरबदल कर अनुसूचित क्षेत्रों लागू कर सकता है। यह देश का पहला कानून है जो आदिवासी इलाकों में नेमी तौर पर सीधे लागू नहीं हुआ।अनुसूचित क्षत्रों में पेसा कानून की धारा 4(घ) के तहत ग्राम सरकार एवं स्वशासी जिला सरकार का गठन करते हुए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार उन्हें हस्तांतरित किया जायेगा तथा संविधान के अनुच्छेद 243 (छ), 243 (ज) एवं 275(1) के अंतर्गत उन्हें समस्त निधि के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण हेतु सक्षम बनाया जाय ताकि स्वायत्त शासन की संवैधानिक भावना चरितार्थ हो।परन्तु राज्य की सत्ता पूर्ण नियंत्रण चाहती है। गांधी के गांव गणराज्य का सपना केवल ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने से पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए सत्ता, संसाधन और निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति गांव समाज तक पहुंचानी होगी। ग्राम सभा को केवल योजनाओं पर चर्चा करने वाली संस्था के बजाय स्थानीय शासन की मूल इकाई के रूप में स्थापित करना होगा। विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा की मूल भावना के अनुरूप ग्राम सभा को भूमि, जंगल, जल, खनिज, लघु वनोपज और स्थानीय संसाधनों से जुड़े निर्णयों में वास्तविक अधिकार देना आवश्यक है। विकास की कोई भी योजना स्थानीय समुदाय की सहमति, भागीदारी और सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभावों की पारदर्शी समीक्षा के बिना आगे नहीं बढ़नी चाहिए। भविष्य की दिशा यह भी होनी चाहिए कि ग्राम सभाओं को उनके अधिकारों के साथ पर्याप्त वित्तीय संसाधन और प्रशासनिक क्षमता मिले। केवल अधिकारों की घोषणा पर्याप्त नहीं है। ग्राम सभा के निर्णयों को लागू करने के लिए वित्त, कर्मचारी और संस्थागत व्यवस्था भी उसी के अनुरूप विकसित करनी होगी। राज्य सरकारों को पेसा कानून के अनुरूप अपने कानूनों और नियमों की समीक्षा करनी चाहिए। जहां राज्य के कानून और ग्राम सभा के अधिकारों के बीच टकराव है, वहां ग्राम स्वशासन की संवैधानिक भावना को प्राथमिकता देने की जरूरत है। ग्राम सभा के निर्णयों में प्रशासनिक हस्तक्षेप कम करने के साथ-साथ उसके निर्णयों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी विकसित की जानी चाहिए। साथ ही, ग्राम सभाओं को केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित रखने के बजाय स्थानीय विकास की प्राथमिकताएं तय करने का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल संरक्षण, कृषि, वन संरक्षण और आजीविका से जुड़े स्थानीय कार्यक्रमों की योजना गांव समाज की जरूरतों के आधार पर बनाई जाए। इससे विकास ऊपर से थोपे जाने वाली प्रक्रिया के बजाय नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली प्रक्रिया बन सकेगा।

इसके लिए जरूरी है कि ग्राम सभा के अधिकारों के बारे में ग्रामीणों में व्यापक जागरूकता हो। आदिवासी समाज की पारंपरिक संस्थाओं, रीति-रिवाजों और सामुदायिक निर्णय प्रक्रिया को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ जोड़ा जाए। तभी पंचायती राज व्यवस्था और आदिवासी स्वशासन के बीच वास्तविक संबंध स्थापित हो सकेगा। आजादी के लगभग आठ दशक बाद भी गांधी का गांव गणराज्य पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। संविधान ने पंचायतों को स्थान दिया, 73वें संशोधन ने ग्राम सभा को संवैधानिक पहचान दी और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेसा कानून बनाया, लेकिन कानून और जमीन पर उसकी वास्तविक शक्ति के बीच अभी भी बड़ा अंतर दिखाई देता है। गांधी के सपने का भारत ऐसा भारत था जिसमें गांव अपने जीवन, संसाधनों और विकास से जुड़े फैसले स्वयं लेने में सक्षम हों। इसका अर्थ राज्य की भूमिका समाप्त करना नहीं, बल्कि राज्य की भूमिका को ऐसी व्यवस्था में बदलना है जिसमें स्थानीय समाज की स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहें। यदि ग्राम सभा को अधिकार देने के बजाय केवल जिम्मेदारियां दी जाती रहेंगी, यदि संसाधनों पर निर्णय लेने की शक्ति ऊपर के स्तर पर केंद्रित रहेगी और यदि विकास के नाम पर स्थानीय समाज की सहमति को औपचारिकता बना दिया जाएगा, तो गांव गणराज्य का सपना अधूरा ही रहेगा। इसलिए गांधी के सपने को पूरा करने की अगली लड़ाई केवल पंचायत चुनावों की नहीं, बल्कि ग्राम सभा को वास्तविक सत्ता, संसाधन और निर्णय का अधिकार देने की लड़ाई है। लोकतंत्र की मजबूती का रास्ता संसद और विधानसभाओं से होकर गांव तक आता है, लेकिन उसकी वास्तविक बुनियाद गांव के लोगों की सामूहिक निर्णय शक्ति में ही है। गांव को केवल प्रशासन की अंतिम इकाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र की पहली इकाई बनाना ही गांधी के गांव गणराज्य की दिशा में अगला कदम होगा।

राज कुमार सिन्हा
बरगी बांध विस्थापित
एवं प्रभावित संघ

राशिफल

मेष राशि :- कार्य लाभ, आशानुकूल सफलता का हर्ष तथा रुके कार्य अवश्य ही बनेंगे।

वृष राशि :- कार्य योजना पूर्ण होगा, शुभ समाचार से मन प्रसन्न हो, सोचे कार्य अवश्य ही बनेंगे।

मिथुन राशि :- कार्य व्यवसाय में थकावट, बैचेनी, कुछ असफलता के साधन अवश्य ही बनेंगे।

कर्क राशि :- दैनिक व्यवसाय गति मंद रहे, असमर्थता का वातावरण अवश्य बना ही रहेगा।

ीसिंह राशि :- आलोचना से बचिए, कार्यकुशलता से पूर्ण संतुष्ट तथा संतोष बना ही रहेगा।

कन्या राशि :- भोग ऐश्वर्य में समय बीतें, शारीरिक थकावट बेचैनी कार्य में बढ़े ध्यान दे।

तुला राशि :- मित्र वर्ग विशेष फलप्रद रहे, आशानुकूल सफलता से संतोष होगा।

वृश्चिक राशि :- मित्र वर्ग विशेष फलप्रद रहे, कार्य में सफलता प्राप्त हेगी, रुके कार्य बनेंगे।

धनु राशि :- तनाव पूर्ण वातार्लाप चलती रहेगी तथा सुखवर्धक योग अवश्य होगा।

मकर राशि :- कार्य वृत्ति में सुधार, सामाजिक कार्य में मान प्रतिष्ठा अवश्य ही बन जाएगी।

कुंभ राशि :- कार्य व्यवसाय गति मंद, चोट आदि का भय रहेगा तथा मानसिक तनाव बनेगा।

मीन राशि :- आशानुकूल सफलता का हर्ष, बिगड़े कार्य की योजना अवश्य ही बनेगी।

गैलेक्सी हॉस्पिटल में जन्मजात हृदय रोग का सफल ऑपरेशन; आयुष्मान योजना से हुआ निःशुल्क उपचार

टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट नामक गंभीर जन्मजात हृदय रोग का सफल ऑपरेशन, चिकित्सकों की टीम के सामूहिक प्रयास रंग लाए



जबलपुर। उखरी रोड स्थित गैलेक्सी मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल में टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट नामक गंभीर जन्मजात हृदय रोग का 1 वर्ष की बच्ची काव्या का सफल ऑपरेशन किया गया। अस्पताल के चिकित्सक डॉ. अखिलेश दुबे, डॉ. प्रीतम सांगवान,डॉ श्रीधर,डॉ. विवेक गुप्ता और उनकी टीम के अथक प्रयासों से यह सर्जरी सफल हुई। उल्लेखनीय है मरीज का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क किया गया। चिकित्सकों के अनुसार टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट एक जन्मजात दिल की स्थिति है जिसमें चार प्रमुख दोष होते हैं – वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट , पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग एओर्टा और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इन कमियों के कारण शरीर में ऑक्सीजनयुक्त और ऑक्सीजनहीन खून का मिश्रण हो जाता है, जिससे बच्चों में साइनोसिस (नीला रंग पड़ना), टेट स्पैल्स (अचानक ऑक्सीजन कम होना), और जल्दी थकना जैसे लक्षण दिखते हैं। इस रोग का स्थायी इलाज ऑपरेशन ही माना जाता है और अक्सर बच्चे के पहले वर्ष के भीतर सर्जरी कराई जाती है। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर पहचान और विशेषज्ञ सर्जरी से मरीजों की जीवन प्रत्याशा और जीवन-गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार होता है।गैलेक्सी मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल ने विशेष रूप से आयुष्मान योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए इस जरूरी सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा किया। डॉक्टर्स ने कहा, ह्लळडऋजैसे कॉम्प्लेक्स कार्डियक मामलों में समय पर पहचान और सर्जिकल इंटरवेंशन जीवन बदल देता है। पूरा ऑपरेशन टीमवर्क था – सर्जरी, एनेस्थीसिया, नर्सिंग और आईसीयू स्टाफ सबने बेहतरीन समन्वय दिखाया।मैनेजमेंट टीम ने कहा, हमारा लक्ष्य समय पर सही निदान और उच्च गुणवत्ता वाली सर्जरी देकर बच्चों को एक सामान्य और स्वस्थ जीवन देना है।ह्व अस्पताल ने आगे भी इस तरह के कार्डियक मामलों के लिए जागरूकता और स्क्रीनिंग बढ़ाने का आश्वासन दिया।

अस्पताल ने ऑपरेशन में सहयोग देने वाले समस्त मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ का धन्यवाद ज्ञापित किया है। परिजन और स्थानीय समुदाय ने भी अस्पताल तथा डॉक्टरों की टीम की सराहना की है।

टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट क्या है?

इस बीमारी में दिल की बनावट में चार मुख्य कमियां होती हैं। इन कमियों के कारण शरीर में ऑक्सीजन वाले साफ खून और बिना ऑक्सीजन वाले गंदे खून का मिश्रण होने लगता है, जिससे पूरे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती।

वे चार कमियां इस प्रकार हैं:

वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट : दिल के नीचे के दो कोनों के बीच की दीवार में छेद होना।

पल्मोनरी स्टेनोसिस : फेफड़ों तक खून ले जाने वाली नली और वाल्व का सिकुड़ या छोटा जाना, जिससे फेफड़ों में खून कम जा पाता है।

ओवरराइडिंग एओर्टा : शरीर को खून सप्लाई करने वाली मुख्य महाधमनी अपनी सही जगह से थोड़ा हटकर सीधे उस छेद के ऊपर आ जाती है।

राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी : ज्यादा जोर लगाने के कारण दिल के दाहिने हिस्से की मांसपेशी का मोटा हो जाना।।

वित्त वर्ष 2026 में परिवारों को औसतन 5 लाख का डेथ क्लेम देकर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस सबसे आगे



मुंबई। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने वित्त वर्ष 2026 में परिवारों को औसतन ?15 लाख का व्यक्तिगत डेथ क्लेम (मृत्यु दावा) दिया है। कंपनी लगातार दूसरे साल इस मामले में सबसे आगे रही है, जो समय पर वित्तीय सहायता देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले छह वित्त वर्षों के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध उद्योग आंकड़ों के अनुसार, कंपनी द्वारा भुगतान की गई औसत व्यक्तिगत डेथ क्लेम राशि वित्त वर्ष 2021 के लगभग ?10 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ?15 लाख हो गई है। पिछले चार वर्षों में यह औसत क्लेम लगातार लगभग ?14–15 लाख के आसपास बना हुआ है। जैसे-जैसे आय, कर्ज और पारिवारिक जिम्मेदारियां बदलती हैं, ये आंकड़े रेखांकित करते हैं कि पॉलिसीधारकों को समय-समय पर अपने लाइफ कवर (जीवन बीमा राशि) की समीक्षा क्यों करनी चाहिए, ताकि यह उनकी बदलती जरूरतों के अनुकूल बना रहे।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में अंडरराइटिंग एंड रिटेल क्लेम्स के प्रमुख सारंग गोखले ने कहा, "जीवन बीमा एक सरल वादे पर आधारित है—परिवारों को उस समय वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना, जब उन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत हो। वित्त वर्ष 2026 में हमने 5,149 करोड़ रुपये के मृत्यु दावों का निपटारा किया। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2026 में हमारा दावा निपटान अनुपात 99.3 प्रतिशत रहा। कंपनी स्तर पर जांच नहीं किए गए व्यक्तिगत दावों में अंतिम दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से औसत निपटान समय केवल 1.1 दिन रहा। यह हमारे ग्राहकों और उनके परिवारों से किए गए वादे को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम दावों की प्रक्रिया को लगातार सरल बना रहे हैं और तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि परिवारों को बिना किसी देरी के आवश्यक सहायता मिल सके। हम अपने ग्राहकों को यह भी सलाह देते हैं कि वे नियमित रूप से अपने बीमा कवर की समीक्षा करें, ताकि यह उनके जीवन के बदलते चरणों और लक्ष्यों के अनुरूप बना रहे।"

विशेष रूप से, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने पिछले कई वर्षों में लगातार उच्च क्लेम सेटलमेंट रेशियो दर्ज किया है और समय पर क्लेम का भुगतान करने के अपने वादे को निभाया है। अपने कवर की समीक्षा या सहायता के इच्छुक पॉलिसीधारक ६६६८-ूस्र१४ी ूब्रे पर जा सकते हैं या कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।



ड़ी डिटर्जेंट का नया कैंपेन विश्वास की परीक्षा लॉन्च, ग्राहकों के भरोसे को और मजबूत

माधुरी दीक्षित बनीं घड़ी डिटर्जेंट की नई ब्रांड एंबेसडर, बेहतर डिटर्जेंट के साथ नई शुरूआत

सतना। आरएसपीएल ग्रुप ने घड़ी डिटर्जेंट का नया कैंपेन विश्वास की परीक्षालॉन्च किया है। इस कैंपेन में बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षितघड़ी डिटर्जेंट की ब्रांड एंबेसडर हैं। इस नए कैंपेन का संदेशहै, विश्वास की खास बात यही है कि उस पर हमेशा खरा उतरना पड़ता है। कैंपेन मेंबताया गया है कि घड़ी डिटर्जेंट अपने ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने के लिए अपने डिटर्जेंट प्रोडक्ट्स और उसके इस्तेमाल के अनुभव को लगातार बेहतर बनायाहै। यह कैंपेन घड़ी डिटर्जेंट केतैयारकिएगएनए फॉर्मूलेशन पर आधारित है। इसे लोगों के कपड़े धोने के बदलते तरीके को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कैंपेन फिल्म में विश्वास की परीक्षा के जरिए नए घड़ी डिटर्जेंट की सफाई और गुणवत्ता को दिखाया गया है। फिल्म में माधुरी दीक्षित घड़ीडिटर्जेंट के नए पैक के साथ नजर आ रही हैं। नए घड़ी डिटर्जेंट को कई तरह की परीक्षाओं से गुजरते हुए दिखाया गया है। इसमें बारीकडिटर्जेंट पाउडर, पानी में जल्दी घुलना, ज्यादा झाग और कपड़ों की बेहतर सफेदी जैसी खूबियां दिखाई गई हैं। नए अंदाज में पेश किए गए घड़ीडिटर्जेंट के इस कैंपेन में ब्रांड की पुरानी टैगलाइन पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें को भी बरकरार रखा गया है। इसके जरिए लोगों को खुद घड़ीडिटर्जेंट इस्तेमाल करने और इसके फर्क को महसूस करने के लिए कहा गया है। कैंपेन में घड़ी डिटर्जेंट की तीन खास खूबियों पर जोर दिया गया है:ः 2 फोम टेक्नोलॉजीः हाथ से या बाल्टी में कपड़े धोते समय ज्यादाऔरदोगुनाझागबनताहै, जिससे गंदगी और दाग आसानी से निकलते हैं। सुपर पाउडर फॉर्मूलाः इसका बारीक पाउडर कपड़े के रेशों तक गहराई से पहुंचता है और जमी हुई गंदगी को साफ करने में मदद करता है। जल्दी घुलने वाला फॉर्मूलाः पानी में जल्दी घुल जाता है, जिससे कपड़ों की बेहतर सफाई होती है। घड़ी डिटर्जेंट की कीमत और अलग-अलग पैक साइज भी ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट चुनने का विकल्प देते हैं। इसी वजह से ब्रांड अपनी बेहतर सफाई और किफायती कीमत के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने और उन्हें इसे आजमाने के लिए आकर्षित करने पर जोर दे रहा है। इस लॉन्च के मौके पर आरएसपीएल ग्रुप के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल ज्ञानचंदानी ने बताया कि, घड़ी में हमाराहमेशा से ये मानना है कि नए बदलाव का फायदा लोगों को रोजमर्रा के इस्तेमाल में साफ दिखना चाहिए।



पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें

छिंदवाड़ा चौक पर पुलिस की चेकिंग, आठ वाहन चालकों पर कार्रवाई

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से वसूला समन शुल्क



दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए कोतवाली पुलिस ने शहर के छिंदवाड़ा चौक पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। 29 और 30 सितंबर को की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले आठ वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन चालकों से समन शुल्क वसूला गया। इसके साथ ही वाहन चलाते समय आवश्यक दस्तावेज साथ रखने और यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा एवं संबंधित अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई में प्रशिक्षु डीएसपी सचिन मुहानिया, कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी एवं पुलिस स्टाफ की भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चेकिंग और वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

राज्य स्तरीय बॉक्सिंग में सिवनी के खिलाड़ियों ने जीते पांच पदक

पांच पदकों से चमका सिवनी का नाम



दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- राज्य स्तरीय शालेय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सिवनी के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए तीन रजत और दो कांस्य पदक हासिल किए। भोपाल के टी.टी. नगर स्टेडियम में 27 से 30 सितंबर तक हुई प्रतियोगिता में सिवनी के 10 खिलाड़ियों ने जिले का प्रतिनिधित्व किया। बालिका वर्ग में श्रुति सिंह राजपूत ने 42 किग्रा और अवनी चौरसिया ने 54-57 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। उत्कर्षा राउत ने 40-52 किग्रा तथा भावना शर्मा ने 63-66 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। बालक वर्ग में प्रीत साहू ने 17 वर्ष, 48-50 किग्रा वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में फाज़िल खान (36-38 किग्रा), अंश यादव (42-44 किग्रा), अभिनव सिंह (48-50 किग्रा), अंजल अली खान (63-69 किग्रा) और वैभव राय (46 किग्रा) ने भी सिवनी का प्रतिनिधित्व किया।

सोहन सेन रहे संभागीय कोच

सिवनी के बॉक्सिंग प्रशिक्षक एवं जिला बॉक्सिंग संघ के सचिव सोहन लाल सेन को प्रतियोगिता में जबलपुर संभाग की टीम का कोच बनाया गया था। उनके मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में मुकाबले खेले। सिवनी के पदक विजेता खिलाड़ी नियमित रूप से सेन से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न संभागों से करीब 600 खिलाड़ी और 100 से अधिक ऑफिशियल व कोच शामिल हुए। सिवनी के खिलाड़ियों की पदक उपलब्धि पर जिला शिक्षा अधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी जस्सी थॉमस, जिला बॉक्सिंग संघ अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी सहित खेल जगत से जुड़े लोगों ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षक को बधाई दी।

नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत

बाल अधिकार संगठन ने बताया ऑनलाइन सुरक्षा की दिशा में अहम पहल

दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए निर्देश का सिवनी में बाल अधिकारों के लिए काम कर रहे नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड यूथ डेवलपमेंट ने स्वागत किया है। संगठन ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए भारतीय कानूनों का प्रभावी पालन जरूरी है। दरअसल, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ऐसे वैधानिक प्रावधानों पर विचार करने को कहा है, जिनसे नाबालिगों से जुड़े भारतीय कानूनों का पालन सुनिश्चित हो सके। याचिका में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय लागू करने की मांग की गई थी। संगठन की कार्यक्रम निदेशक दीप्ति दिवान ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों को यौन शोषण, ट्रैफिकिंग, सेक्सटॉर्शन, साइबर बुलिंग और निजी डेटा के दुरुपयोग जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय करने और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे। सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ स्वतंत्र रूप से अनुबंध करने के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा के पालन का मुद्दा भी सामने आया। पीठ ने केंद्र से इस विषय को इंटरमीडियरी नियमों के दायरे में शामिल करने पर विचार करने को कहा। संगठन के जिला कार्यक्रम समन्वयक संजय मिश्रा ने बताया कि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड यूथ डेवलपमेंट, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस के सहयोगी संगठन के रूप में सिवनी में बाल अधिकारों के संरक्षण को लेकर काम कर रहा है।

एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ : सुनीता सनोडिया और कमलकिशोर चौधरी सम्मानित

फार्मर रजिस्ट्री और वन विभाग के कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिला सम्मान





दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- जिले में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना की पहल पर शुरू की गई एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ योजना के तहत सितंबर माह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पटवारी सुनीता सनोडिया और कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी कमलकिशोर चौधरी को सम्मानित किया गया। तहसीलदार कार्यालय सिवनी में पदस्थ पटवारी सुनीता सनोडिया को फार्मर रजिस्ट्री में बेहतर कार्य के लिए सम्मान मिला। उपलब्ध 1017 बकेट में से उन्होंने 605 बकेट क्लियर किए, जो 59.39 प्रतिशत है। इसी तरह दक्षिण सिवनी वनमंडल में पदस्थ कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी कमलकिशोर चौधरी को वन विभाग से जुड़े विभिन्न कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने वन भू-अभिलेख, वन संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, परिवेश पोर्टल, वन अधिकार अधिनियम, वन एवं राजस्व सीमा विवाद तथा वन व्यवस्थापन से जुड़े कार्यों का दायित्व संभाला। चौधरी ने वनग्राम, गैर-वन भूमि की अधिसूचना, खनिज एवं अतिक्रमण प्रकरण, एनओसी पोर्टल, स्टोर रिटर्न तथा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़े प्रकरणों पर भी कार्य किया। इसके अलावा ओएफसी लाइन, पेयजल पाइपलाइन, कार्य आयोजना क्रियान्वयन और विभागीय ऑनलाइन पोर्टलों से जुड़े कार्यों में भी उनकी भूमिका रही। कलेक्टर ने कहा कि मैदानी स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की मेहनत से प्रशासन की कार्यक्षमता और जनसेवा की गुणवत्ता बेहतर होती है। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान मिलने से उनका मनोबल बढ़ता है और अन्य कर्मचारियों को भी बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ पहल के माध्यम से जिले में जवाबदेही, उत्कृष्ट कार्य संस्कृति और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। हर माह विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

उगली में भारतीय किसान संघ का अभ्यास वर्ग, किसानों की समस्याओं पर हुई चर्चा

राजस्व प्रकरणों के सुधार से लेकर धान खरीदी तक उठीं मांगें



दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी - भारतीय किसान संघ मध्यप्रदेश, महाकौशल प्रांत जिला सिवनी के तत्वावधान में बुधवार को ग्राम पंचायत उगली के सामुदायिक भवन में अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत भारत माता एवं भगवान बलराम के पूजन-अर्चन से हुई। इसके बाद पदाधिकारियों एवं उपस्थित किसानों का परिचय कराकर संगठन की गतिविधियों और किसान हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। अभ्यास वर्ग में प्रांतीय संगठन मंत्री तुलाराम, जिला अध्यक्ष ज्वाला सिंह, जिला मंत्री मेहतालाल, प्रभारी मंत्री गेंदलाल, केवलारी तहसील अध्यक्ष शिवप्रसाद, वरिष्ठ कृषक मूरतलाल, सचिव चितरंजन सहित उगली, मोहबर्रा, सरेखा और पां. छपारा मंडलों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। बैठक में किसानों की समस्याओं और संगठन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। किसानों का कहना था कि बढ़ती महंगाई और कृषि लागत के बीच उन्हें उनकी मेहनत का उचित लाभ मिलना जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में उगली मंडल अध्यक्ष की ओर से किसान हित से जुड़ा ज्ञापन पढ़कर सुनाया गया।

धान खरीदी व्यवस्था में बदलाव की मांग

ज्ञापन में राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष सुधार शिविर लगाने, रुमाल एवं बरगुर पिकअप बियर बांध की नहरों का सीमेंटीकरण एवं आवश्यक मरम्मत कराने की मांग रखी गई। उगली में धान खरीदी को लेकर भी किसानों ने अपनी बात रखी। किसानों ने मांग की कि धान खरीदी मंडी परिसर में ही कराई जाए। खेल मैदान में धान खरीदी केंद्र संचालित नहीं किया जाए, क्योंकि इससे विद्यालय स्तर पर खेल गतिविधियां और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। किसानों ने संबंधित सहकारी समितियों को ही धान उपार्जन का कार्य सौंपने की मांग भी रखी।

संगठन विस्तार पर जोर

बैठक में प्रत्येक मंडल के अंतर्गत समितियों का गठन कर किसान हित के मुद्दों पर लगातार चर्चा करने और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि किसानों को उनके हक और अधिकार की जानकारी देने के साथ उनकी समस्याओं को संगठित रूप से उठाना जरूरी है। जिला मंत्री मेहतालाल ने हरछठ पर्व और भगवान बलराम जयंती के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान बलराम को किसान दिवस के रूप में भी स्मरण किया जाता है। उन्होंने भगवान बलराम के हाथ में हल और मूसल के प्रतीकात्मक महत्व की जानकारी किसानों को दी। कार्यक्रम के अंत में संगठन के पदाधिकारियों ने उगली मंडल में अभ्यास वर्ग के आयोजन की सराहना की। मंच संचालन उगली मंडल मंत्री राजदीप ने किया तथा आभार व्यक्त किया गया।

गणेश उत्सव समितियों का सम्मान, तीन समितियां पुरस्कृत

शांतिपूर्ण आयोजन के लिए 19 समितियों को भी सांत्वना पुरस्कार



दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- नगर में 14 से 25 सितंबर तक आयोजित श्रीगणेशोत्सव के शांतिपूर्ण एवं सफल आयोजन के बाद जिला युवा संधि समाजसेवी संस्था द्वारा बुधवार रात काली चौक में सार्वजनिक गणेश उत्सव समितियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आयोजन में शास्त्रगत विधि-विधान, अनुशासन और शांतिपूर्ण चल समारोह के साथ प्रतिमा विसर्जन करने वाली समितियों को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार छिंदवाड़ा रोड कुचबुंदिया मोहल्ला समिति, द्वितीय पुरस्कार लालबाग के महाराजा गणेश उत्सव समिति, सुभाष वार्ड तथा तृतीय पुरस्कार बाल समाज गणेश उत्सव समिति, केवटी वार्ड को प्रदान किया गया। इसके अलावा 19 गणेश उत्सव समितियों को सफल आयोजन के लिए सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माता महाकाली की आरती-पूजन से हुआ। इसके बाद मुख्य अतिथि एसडीओपी चंचलेश मरकाम, सीएसपी सचिन, कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी, डूंडासिवनी थाना प्रभारी चैनसिंह उइके, सुरेंद्र करोसिया, विनोद जैन, श्रीकांत दुबे एवं कार्यक्रम अध्यक्ष सुबोध बाझल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रितिका सोनी ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया। समारोह में नगर की व्यायामशालाओं से जुड़े स्वयंसेवकों का भी शाल-श्रीफल से सम्मान किया गया। संस्था की ओर से श्रीकांत दुबे ने बताया कि समितियों के चयन में शास्त्रगत विधि-विधान, अनुशासन, हुड़दंग से दूरी और प्रशासन के सहयोग जैसे बिंदुओं को आधार बनाया गया।

दुर्गा उत्सव को लेकर रखीं मांगें

समारोह में गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों ने प्रतिमा विसर्जन के दौरान आने वाली परेशानियों का मुद्दा उठाया। समितियों ने बैनगंगा नदी के लखनवाड़ा घाट की सफाई एवं गहरीकरण कराने की मांग रखी, ताकि आगामी धार्मिक आयोजनों में प्रतिमाओं का व्यवस्थित विसर्जन हो सके। इसके साथ ही दुर्गा उत्सव के दौरान नेहरू रोड पर शाम 7 से रात 11 बजे तक चौपहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित करने की मांग भी रखी गई। उपस्थित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने पर्व के दौरान आवश्यक व्यवस्था किए जाने का आश्वासन दिया। मुख्य अतिथि एसडीओपी चंचलेश मरकाम ने कहा कि गणेश उत्सव का शांतिपूर्ण आयोजन पुलिस प्रशासन और समितियों के आपसी सहयोग से संभव हुआ है। उन्होंने आगामी दुर्गा उत्सव भी धार्मिक गरिमा एवं शांति के साथ संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक सहयोग का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम के आयोजन में जिला युवा संधि समाजसेवी संस्था के अध्यक्ष दिलीप नेमा सहित राजेंद्र गुप्ता, विनोद सतनामी, मनोज ब्रह्मवंशी, राजा ठाकुर, सोहन सोनी, धनराज यादव, अमित तिवारी, संदीप सोनी, नरोत्तम साहू, प्रदीप सराठे, सिद्धार्थ ताम्रकार, रितेश पटेल, शिव कहार, अरुण श्रीवास्तव, अमोल शुक्ला, रामगोपाल चौधरी, कन्हैया नाविक एवं अमित का सहयोग रहा। मंच संचालन बसंत बघेल ने किया। कार्यक्रम अध्यक्ष सुबोध बाझल ने प्रशासन, पुलिस, गणेश उत्सव समितियों, व्यायामशाला समितियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

सिवनी में धारा 163 लागू, धरना-जुलूस से सोशल मीडिया तक प्रतिबंध



दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- जिले में कानून-व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती नेहा मीना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (इठरर) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली, सार्वजनिक आयोजनों और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को लेकर कई पाबंदियां लागू की गई हैं। आदेश के अनुसार सक्षम अनुमति के बिना धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली अथवा अन्य सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। आयोजन की अनुमति के लिए निर्धारित समय से पहले संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना आवश्यक होगा। धार्मिक या सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री के साथ आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो, वीडियो, कमेंट और संदेशों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने, साझा करने या फॉरवर्ड करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले नारे, पोस्टर, बैनर और गीतों के उपयोग पर रोक रहेगी। सार्वजनिक कार्यक्रमों में शस्त्र प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है। सक्षम अनुमति के बिना डीजे, लाउडस्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा सड़क और चौराहों पर वाहन, ठेले अथवा अन्य सामग्री खड़ी कर आवागमन बाधित करने पर भी रोक रहेगी। आदेश 30 सितंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू होकर दो माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल आएंगे भोपाल

लखपति गोपालक दीदी योजना पशुपालन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की बढ़ेगी आय

राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में पशुपालक दीदियों के सम्मान के साथ विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे शुभारंभ व अनुदान राशि का वितरण



भोपाल। सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह 3 अक्टूबर को भोपाल आएंगे। वे भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित ह्यराज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन' में शामिल होकर उत्कृष्ट कार्य करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और 'डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना' के स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे। इसके साथ ही वे प्रदेशवासियों को डेयरी प्रसंस्करण, दुग्ध संयंत्र और गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला से जुड़ी विभिन्न विकास सौगातों की सौगात देंगे।

सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री श्री शाह 255 करोड़ रुपये की लागत से उज्जैन में बनने वाले नए डेयरी प्लांट का भूमिपूजन करेंगे। इसके अतिरिक्त, 16.80 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित फर्मेंटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट और एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन भोपाल में ह्यनेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट' के तहत 12.40 करोड़ रुपये की लागत से बनी अत्याधुनिक प्रयोगशाला एंव मिनी डेयरी संयंत्र शिवपुरी का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ के दुग्ध उत्पादकों को लगभग 12 करोड़ रुपये की बोनस राशि वितरित की जाएगी तथा ह्यकृषक कल्याण वर्ष' के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा विशेष प्रदर्शनी भी लगायी जाएगी।

प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत एवं संचालित गौशालाओं में संरक्षित गोवंश के रखरखाव एवं भरण-पोषण के लिए माह जुलाई और अगस्त 2026 की 101 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में हस्तांतरित की जाएगी। यह राशि गौशालाओं में दर्ज गोवंश के समुचित व्यवस्थापन, आहार एवं भरण-पोषण के लिए दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत एवं संचालित गौशालाओं में संरक्षित गोवंश के लिए 40 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है।

महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा संबल : लखपति गोपालक दीदी योजना पशुपालन से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। बेहतर आनुवंशिक क्षमता वाले पशुओं के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, अतिरिक्त आय के अवसर और पशुपालन की उत्पादकता बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। योजना का उद्देश्य पशुपालन को केवल पारंपरिक आजीविका तक सीमित न रखते हुए इसे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और समृद्धि का माध्यम बनाना है।

प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को पशुपालन के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से ह्यलखपति गोपालक दीदी योजनाह्न का संचालन किया जा रहा है। ह्यशून्य पूंजीगत निवेश, अधिकतम आनुवंशिक एवं आर्थिक लाभह्न के मूल मंत्र पर आधारित इस योजना से प्रदेश की 2 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। योजना के तहत अवर्णित (नॉन-डिस्क्रिप्ट) नस्ल की गायों और भैंसों मंप उच्च नस्ल के सीमन से कृत्रिम गभार्धान को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे पशुपालकों को बिना अतिरिक्त खर्च के बेहतर आनुवंशिक क्षमता वाले पशु प्राप्त हो रहे हैं।

भोपाल में आदर्श गौ शाला स्थापित करने के कार्य को शीघ्र पूर्ण करें: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

विभागों की योजनाओं पर हुई चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं पर चर्चा की। इन विभागों में नगरीय विकास एवं आवास, खनिज, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को हुई बैठक में विभागों के अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति और कार्यों की जानकारी प्राप्त की और जरूरी दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री नीरज मंडलोई सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा प्रदेश के नगरों के साथ ही राजधानी भोपाल के विकास में नए आयाम जोड़े जाएं। ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन में बड़ी आदर्श गौशालाओं के संचालन में सफलता मिली है। इसी तरह भोपाल में इस मॉडल पर आदर्श गौ-शाला स्थापित करने के कार्य को गति प्रदान करते हुए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंगरौली को आदर्श जिला बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों से भी चर्चा की जाए। नई टाउनशिप विकसित होने से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और सभी वर्ग लाभान्वित होंगे। खनिज विभाग के अधिकारियों ने सिंगरौली जिले में माइनिंग सेक्टर की नई संभावनाओं और भविष्य में जिले के समग्र विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की। बैठक में बताया गया कि सिंगरौली में अधोसंरचना विकास के कार्य हो रहे हैं। सिंगरौली विकास प्राधिकरण की गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है।

निजी क्षेत्र में आईटी पार्क स्थापना को प्रोत्साहित करें : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित चर्चा में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि निजी क्षेत्र में भी आईटी पार्क स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए। जबलपुर के उद्यमी सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कार्य के इच्छुक हैं। इस नाते उन्हें मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया जाए। इसके अलावा टेक्नीकल यूनिवर्सिटी को एक महत्वपूर्ण कौशल विकास केंद्र की पहचान देने के प्रयास किए जाएं। बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश जल जीवन मिशन के कार्यों में अग्रणी है। प्रदेश के 83 लाख से अधिक परिवारों को नल से जल मिल रहा है। गत दो वर्ष में इस कार्य में अच्छी सफलता मिली है। प्रदेश की 38 हजार 403 जल प्रदाय संरचनाओं को जियो टैग किया गया है।

आठ लोगों की सहमति पूरे समाज का फैसला नहीं-हाजी हारून

बोले-शाही मस्जिद महाकाल मंदिर से दूर, कोर्ट को गुमराह किया; दूसरे विकल्पों पर विचार क्यों नहीं हुआ

भोपाल। उज्जैन शाही मस्जिद विवाद में जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने प्रशासन और अदालत में रखे गए तथ्यों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शाही मस्जिद को महाकाल मंदिर के बिल्कुल करीब बताकर कोर्ट को गुमराह किया गया। उनका दावा है कि मस्जिद मंदिर से काफी दूरी पर है और सड़क चौड़ीकरण के लिए केवल तीन फीट जगह की जरूरत थी तो दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता था। हारून ने यह भी कहा कि प्रशासन के साथ करीब आठ लोगों की बातचीत या सहमति को पूरे मुस्लिम समाज की सहमति नहीं माना जा सकता। उनके मुताबिक, ऐसे संवेदनशील मामले में आम लोगों को पूरी स्थिति बताकर भरोसे में लेना चाहिए था।

कोर्ट में पूरे तथ्य रखे जाते तो तस्वीर अलग होती : हारून ने कहा कि अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान मौके की वास्तविक स्थिति और सभी तथ्य सही तरीके से रखे जाना जरूरी है। उनका कहना है कि शाही मस्जिद को महाकाल मंदिर के बिल्कुल करीब बताना सही नहीं है। यदि अदालत के सामने पूरी जानकारी रखी जाती तो मामले की तस्वीर अलग हो सकती थी। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मामले में पहले सिंगल बेंच और फिर डबल बेंच में सुनवाई हुई। ऐसे में पक्षकारों को उपलब्ध न्यायिक विकल्पों का इस्तेमाल करने का अवसर मिलना चाहिए था। उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या जल्दी थी कि मामले को अंतिम न्यायिक स्तर तक जाने का मौका नहीं दिया गया।

तीन फीट जगह के लिए दूसरे विकल्प क्यों नहीं : हारून ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के लिए यदि केवल तीन



फीट जगह की जरूरत थी तो प्रशासन को दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए था। उन्होंने शाही मस्जिद के सामने मौजूद संदल वाली इमारत को भी विकल्प बताया। उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर मुआवजा देकर दूसरी संपत्ति ली जा सकती थी और मुस्लिम समाज इसके लिए राशि जुटाने को तैयार था। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के लिए रास्ते का डिजाइन बदलने, गलियों को चौड़ा करने या आसपास की अन्य संपत्तियों को लेने जैसे विकल्प भी देखे जा सकते थे। उनका कहना है कि विकास कार्य में मंदिर या मस्जिद को हटाने के बजाय धार्मिक स्थलों को बचाकर रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए।

सहमति बनी थी तो आम लोगों को बताना था : हारून ने प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच हुई बातचीत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार करीब आठ लोगों ने प्रशासन से बातचीत की थी। यदि कोई सहमति बनी थी तो आम लोगों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए था कि क्या तय हुआ और मस्जिद का कितना हिस्सा प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि मस्जिद की सुरक्षा के लिए लंबे समय से लोग वहां मौजूद थे। ऐसे में अचानक कार्रवाई के बजाय पहले उन्हें वास्तविक स्थिति समझाई जानी चाहिए थी। हारून ने कहा कि कुछ लोगों का प्रशासन से बात कर लेना पूरे मुस्लिम समाज की सहमति नहीं माना जा सकता।

कार्रवाई में नुकसान की जांच की मांग : हारून ने मस्जिद की मीनार हटाने के तरीके पर भी सवाल उठाया। उनका आरोप है कि जिस हिस्से को मैनुअल तरीके से हटाने की बात थी, वहां मशीनों के इस्तेमाल से मीनार गिर गई और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। उन्होंने इसकी जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग की। उन्होंने शाही मस्जिद के अलावा तकिया मस्जिद को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि पार्किंग के लिए धार्मिक स्थल हटाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार होना चाहिए था।

मप्र से 2-3 दिन में मानसून की विदाई

अब केवल बूंदाबांदी के ही आसार; कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं

भोपाल। मध्य प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई 2 से 3 दिन में हो सकती है। IMD (मौसम केंद्र) ने यह संकेत दिए हैं। मौसम विशेषज्ञ शैलेंद्र कुमार नायक के मुताबिक, 3 दिन तक नमी की वजह से बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन किसी भी जिले में भारी बारिश का अनुमान नहीं है। इधर, एमपी में मानसूनी पीरियड खत्म हो गया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून का पीरियड 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है। आखिरी एक सप्ताह में अति भारी या भारी बारिश नहीं हुई। इस वजह से प्रदेश के 55 में से 30 जिलों में सामान्य बारिश का कोटा पूरा नहीं हुआ है। भोपाल, ग्वालियर समेत



25 जिलों में ही कोटा फुल हुआ है। आलीराजपुर में तो सामान्य की आधी बारिश भी रिकॉर्ड नहीं हुई, जबकि निवाड़ी-मऊगंज में 150% से ज्यादा पानी गिर गया।

अब जो बारिश वह बोनस जैसी : प्रदेश से जब तक मानसून की विदाई नहीं हो जाती, तब तक बूंदाबांदी का दौर चलेगा, जो बोनस की तरह रहेगी। मौसम विभाग इसे मानसूनी सीजन की बारिश में दर्ज नहीं करेगा।

आज इन जिलों में बूंदाबांदी, गरज-चमक का अनुमान : मौसम विभाग ने गुरुवार को मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में बूंदाबांदी और गरज-चमक का अनुमान जताया है। वहीं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर समेत अन्य जिलों में तेज धूप खिली रहेगी।

छात्रा की पिटाई करने वाली पीएचई सब इंजीनियर पर एफआईआर

रायसेन में वीडियो जारी कर मांगी माफी; बोली- ऑफिस के काम से परेशान थी

रायसेन। रायसेन के मुखर्जी नगर गेट के पास छात्रा से मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को महिला रंजना ठाकुर पर केस दर्ज कर लिया। पीएचई विभाग में सब इंजीनियर रंजना की पहचान कार नंबर से हुई। पुलिस ने उसे थाने बुलाकर पूछताछ कर समझाया। घटना के बाद महिला ने वीडियो जारी कर छात्रा व उसके परिवार से माफी मांगी। यह घटना बुधवार को हुई थी और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पीड़ित परिवार की शिकायत



पर पुलिस ने मारपीट और गाली-गलौज की धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी महिला ने वीडियो जारी कर माफी मांगी। उसने वीडियो में कहा कि वह ऑफिस के काम से परेशान थी। छात्रा से कुछ गलती हुई, पर उसे बच्ची की उम्र का अंदाजा नहीं था। गुस्से में हाथ उठ गया, इसके लिए वह माफी मांगती है और ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। कोतवाली थाना प्रभारी नरेंद्र गोयल ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर नामजद केस दर्ज कर जांच चल रही है।

नागरिकों को त्वरित सेवाएं देने के लिए"सरकार आपके द्वार अभियान

जन-विश्वास अभियान से जुड़ा सेवा सेतु

भोपाल। नागरिकों को पारदर्शी, संवेदनशील, उत्तरदायी एवं समयबद्ध लोक सेवाएँ सीधे उनके गाँव व वार्ड स्तर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेशव्यापी "सरकार आपके द्वारह्नअभियानके तहत 3 अक्टूबर शनिवार को विकासखण्ड स्तर तथा 4 अक्टूबर रविवार को नगरीय क्षेत्र में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान प्रदेश में चल रहे व्यापक ह्नसेवा संकल्प अभियानह्न 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय घटक है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टर, कमिश्नर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, आयुक्त नगर पालिका / नगर निगम / नगर पालिका परिषद को निर्देश जारी किए है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य केन्द्र एवं राज्य सरकार की समस्त फ्लैगशिप हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ नागरिकों, विशेषतः कृषकों, ग्रामीणजनों, श्रमिकों, महिलाओं, वंचितों और कमजोर वर्गों को पहुँचाना है। अभियान को ह्नजन-विश्वास अभियानह्न के साथ भी संबद्ध किया गया है, जिससे जनता के बीच सुशासन, पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही के विश्वास का सेतु स्थापित हो सके।

विकासखंड और नगरीय क्षेत्र में आयोजित होंगे शिविर : प्रत्येक जिले के समस्त विकासखण्डों में 3 अक्टूबर को शिविर आयोजित किए जाएंगे। नगरीय क्षेत्र में 4 अक्टूबर को नगर पालिका निगम में जोनवार, नगर पालिका तथा नगर परिषद में शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर स्थल का आयोजनसार्वजनिक एवं सुलभ स्थानों पर किया जाएगा।उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण, जनपद पंचायत परिसर, सामुदायिक भवन या खेल मैदानजहाँ पर्याप्त खुली जगह, पेयजल, छाया तथा आवागमन की सुगम सुविधा हो। शिविरों के लिए लोक सेवा प्रबंधन, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहयोगी विभाग होंगे। कलेक्टर जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो जिला स्तर पर अभियान का समन्वय करेंगे। कैंप के प्रभारी अधिकारी की सहायता के लिये सहायक अधिकारी की नियुक्ति जिला स्तर से की जायेगी।

नई कृषि तकनीक करेगी किसानों को लाभान्वित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

उमरिया को जल्द ही मिलेगी बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट की सौगात

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के साथ अनेक जनहितैषी निर्णय लिए हैं। किसानों को नई तकनीक का लाभ दिया जा रहा है। उमरिया जिला कोयला भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे काला सोना भी कहते हैं। यहां स्थित बांधवगढ़ किला मध्यप्रदेश की शान है। उमरिया जिला प्राकृतिक औषधि और वन्यजीव संपदा से समृद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उमरिया जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष श्री जयपाल सिंह चावड़ा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिले के किसानों को उपज का समुचित मूल्य दिलवाने के लिए नई कृषि तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तम खेती के लिए सिंचाई सुविधाएं बेहद जरूरी है। इसीलिए राज्य सरकार ने हर गांव और हर खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान धान और श्रीअन्न फसलों के उपार्जन के लिए समय रहते पंजीयन कराएं, ताकि एमएसपी का लाभ मिलता रहे। उन्होंने कहा कि इसी सीजन से किसानों को दिन में भी 10 घंटे बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला प्रशासन को किसान चौपाल लगाकर हितग्राहियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं किसान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान गोपालन, दूध उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी फसलों और जैविक-प्राकृतिक खेती को अपनाकर अपनी आय बढ़ाएं। उन्होंने उमरिया के किसानों को बताया कि शीघ्र ही जिले में एक बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू होगी। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला प्रशासन को पंचायत स्तर पर दुग्ध संकलन समितियों के पंजीयन कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों से कस्टम हायरिंग सेंटर और सोलर पंप जैसी कृषक कल्याण योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।

निःशुल्क रजिस्ट्री का लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सेवा कार्य के 25 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में सेवा से संकल्प अभियान जारी है। राज्य सरकार जिलों में जन विश्वास अभियान के जरिए भी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दे रही है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्र के अभिलेखों की निःशुल्क रजिस्ट्री करवाई जा रही है। किसानों को भी इस स्वामित्व योजना का लाभ मिल रहा है। संपत्ति की पक्की रजिस्ट्री मिलने से हितग्राही बैंक लोन और अन्य आवश्यकताओं के लिए इसे उपयोग कर पाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शिक्षित और समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने के लिए राज्य सरकार स्कूली बच्चों को कई सौगातें दे रही है। शासकीय स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी दी गई हैं। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क किताबें, ड्रेस और साइकिलें वितरित की जा रही हैं। प्रदेशभर में सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बलराम कृषि महोत्सव के लिए उमरिया में उपस्थित मंत्री श्री नागर सिंह चौहान और पूर्व मंत्री सुश्री मीना सिंह से भी संवाद किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और स्थानीय जन उपस्थित थे।

झाड़ फूंक कराने गांव पहुंचे युवक की हत्या

सिर, कान के नीचे चोट के निशान; बैतूल में घर का मालिक और भाई हिरासत में

बैतूल। बैतूल के झल्लार थाना क्षेत्र के खोदरी गांव में गुरुवार को 25 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या का मामला सामने आया है। युवक भगत-भूमका (झाड़-फूंक) कराने के लिए गांव आया था। उसका शव गांव के ही एक व्यक्ति के घर में मिला। पुलिस ने संदेह के आधार पर घर के मालिक सुनील और उसके भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। शव की पहचान शेखर पाल पिता दिनेश पाल (25) निवासी पांगरा, थाना कोतवाली क्षेत्र, के रूप में हुई।



झल्लार थाना प्रभारी वहीद खान के मुताबिक, शेखर बुधवार को खोदरी गांव में सुनील के घर आया था। बाद में इसी घर में उसका शव मिला। पुलिस के अनुसार, शेखर के सिर, कान के नीचे और पेट में धारदार हथियार से चोट के निशान पाए गए। प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद झल्लार पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की।

बैतूल से बुलाई फॉरेंसिक टीम : घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बैतूल से फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम को मौके पर बुलाया। टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं मान रही है। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग या छेड़छाड़ से जुड़े विवाद की आशंका सहित अन्य पहलुओं को भी जांच में शामिल किया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। हिरासत में लिए गए दोनों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।

तेज रफ्तार ट्राला ने गौवंश के झुंड को रौंदा, पांच की मौत, दर्जनों घायल

गौशाला के सामने हुई हृदयविदारक घटना सीसीटीवी में कैद, चालक पुलिस हिरासत में



दैनिक रेवांचल टाईम्स, पन्ना। पन्ना जिले के पवई से करीब 7 किलोमीटर दूर कटनी मार्ग स्थित श्री विद्यासागर गौ रक्षा एवं संवर्धन समिति द्वारा संचालित गौशाला के सामने बुधवार, 30 सितंबर की सुबह करीब 7 बजे हृदयविदारक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्राला क्रमांक ठछ 01 अऋ 8485 गौवंश के झुंड में जा घुसा। हादसे में पांच गौवंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों गौवंश घायल बताए जा रहे हैं।

बताया गया कि रोजाना की तरह सुबह गौशाला से गौवंश को चरने के लिए छोड़ा जा रहा था। इसी दौरान कटनी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्राला ने गौवंश के झुंड को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई गौवंश ट्राला के साथ करीब 15 से 20 मीटर तक घिसटते चले गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

सीसीटीवी में कैद हुई घटना : पूरी घटना गौशाला परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर मौजूद चरवाहों और आसपास के लोगों ने ट्राला को रुकवाया। घटना के बाद चालक के भागने का प्रयास करने की बात भी सामने आई, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। घटना की सूचना पवई पुलिस, गौसेवकों और बजरंग दल कार्यकताओं को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुशील कुमार अहिरवार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ट्राला और चालक को अभिरक्षा में लेकर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

गौशाला अध्यक्ष ने की कड़ी कार्रवाई की मांग : घटना की जानकारी मिलने के बाद गौशाला अध्यक्ष नितिन जैन थाना पहुंचे और ट्राला चालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। घटना से गौसेवकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। थाना प्रभारी सुशील कुमार अहिरवार ने पशुपालकों से अपील की कि अनुपयोगी होने पर पशुओं को बेसहारा न छोड़ें, ताकि खुले में घूमने वाले गौवंश इस तरह की दुर्घटनाओं का शिकार होने से बच सकें।

श्रीमद्भागवत कथा में गूंजा आत्मबोध का संदेश, धुंधकारी के उद्धार प्रसंग ने बंदियों को दिखाई सद्मार्ग की राह



दैनिक रेवांचल टाईम्स, पन्ना। सब जेल पवई में जेल प्रशासन द्वारा आयोजित संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा आध्यात्मिक वातावरण में जारी है। कथा के तृतीय दिवस कथा व्यास डॉ. रजनीश शास्त्री ने आत्मदेव के कष्ट एवं धुंधकारी के उद्धार का भावपूर्ण वर्णन करते हुए कर्म, कुसंगति, सत्संग, भक्ति और आत्मचिंतन के महत्व को समझाया। आयोजन के सूत्रधार जेल अधीक्षक अभिमन्यु पाण्डेय हैं। कथा में सब जेल के बंदी एवं जेल स्टाफ यजमान के रूप में सहभागी बने हुए हैं। बंदी और कर्मचारी एक साथ बैठकर श्रद्धा एवं भक्तिभाव से श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा के दौरान जेल परिसर में भक्ति और आध्यात्मिकता का वातावरण दिखाई दे रहा है।

कुसंगति से बचने और सत्संग अपनाने का संदेश : कथा व्यास डॉ. रजनीश शास्त्री ने आत्मदेव एवं धुंधकारी के प्रसंग के माध्यम से बताया कि मनुष्य के कर्म, विचार और संगति उसके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। कुसंगति व्यक्ति को पतन की ओर ले जा सकती है, जबकि सत्संग, भक्ति और आत्मचिंतन जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों, व्यक्ति अपने आचरण और विचारों में बदलाव लाकर सद्मार्ग पर लौट सकता है। धुंधकारी के उद्धार का प्रसंग आत्मबोध और जीवन में सुधार की प्रेरणा देता है।

बंदियों के लिए आत्ममंथन का अवसर बनी कथा : श्रीमद्भागवत कथा के दौरान बंदी और जेल स्टाफ पूरे भक्तिभाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा के माध्यम से उन्हें अपने जीवन का आत्ममंथन करने, गलत संगति एवं नकारात्मक विचारों से दूर रहने तथा सकारात्मक सोच के साथ जीवन को नई दिशा देने की प्रेरणा मिल रही है। जेल अधीक्षक अभिमन्यु पाण्डेय के मार्गदर्शन में आयोजित यह धार्मिक आयोजन बंदियों के बीच आध्यात्मिक चेतना, आत्मचिंतन और सकारात्मक जीवन मूल्यों को बढ़ावा देने का माध्यम बन रहा है। कथा का संदेश रहा कि सही संगति, आत्मबोध और सद्विचारों के साथ व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है।

लक्ष्य के लिए मेहनत करें विद्यार्थी: कलेक्टर

मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान





दैनिक रेवांचल टाइम्स नरसिंहपुर। नरसिंहपुर। गत दिवस कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में आने वाली असफलताओं से निराश होने के बजाय अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें और निरंतर मेहनत करते हुए आगे बढ़ें। शासन विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अनेक सुविधाएं और योजनाएं संचालित कर रही है। इन सुविधाओं का लाभ लेकर विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई, प्रतिभा और भविष्य निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पीएम श्री शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छह मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी वितरित कर सम्मानित किया गया। साथ ही जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पांच प्रतिभागियों तथा संभागीय तैराकी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर उत्साहवर्धन किया गया।

विद्यार्थियों की शिक्षा में दूरी बाधा न बने

कलेक्टर श्रीमती सिंह ने कहा कि जिले के कई गांवों में परिवहन एवं आवागमन की सुविधा सहज नहीं होने के कारण पहले विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज आने-जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। शासन ने विद्यार्थियों की पढ़ाई निरंतर जारी रखने और उनके आवागमन को सुगम बनाने के लिए कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों को निरूशुल्क साइकिल तथा मेधावी विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश लेने पर मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत निरूशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य यही है कि स्कूल या कॉलेज की दूरी बच्चों की पढ़ाई में बाधा न बने। शासन विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। नरसिंहपुर में सांदीपनि विद्यालय भी विद्यार्थियों की शिक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित रूप से बनाया गया है।

विद्यार्थियों को सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

कलेक्टर श्रीमती सिंह ने स्कूटी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए वाहन चलाते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के स्कूटी नहीं चलाएं और अपना लर्निंग लाइसेंस जरूर बनवाएं। स्कूटी चलाते समय हेलमेट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने इस अवसर पर सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि जो विद्यार्थी इस बार सफल नहीं हुए हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वे अभी से मेहनत और लगन के साथ तैयारी करें, ताकि आगे चलकर वे भी सफलता प्राप्त कर सकें। वार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम के साथ उत्तीर्ण होने वाले छह मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी प्रदान की गई। इनमें तेजस्वी विश्वकर्मा एवं इंद्रपाल विश्वकर्मा, कीरत सेन, स्पर्श विश्वकर्मा, स्नेहा साहू तथा हेमंत रजक शामिल हैं।

चित्रकला की पांच प्रतिभाओं का सम्मान

जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में उत्कृष्ट चित्रकला एवं पोस्टर के लिए चयनित पांच प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं उनके चित्र की प्रतिकृति प्रदान कर सम्मानित किया गया। इनमें परी गौतम, मुस्कान चैधरी, प्रियंका मेहरा, काव्या नागरिया, लखपति दीदी तथा आयुषी अहिरवार कक्षा 12वीं गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल साईंखेड़ा- चंद्रयान विषय पर उत्कृष्ट चित्र बनाने वाली प्रतिभागी शामिल हैं। \

पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों का साप्ताहिक पुनर्योवनीकरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न





दैनिक रेवांचल टाईम्स, पन्ना। पन्ना टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र हिनौता अंतर्गत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हाथी कैम्प में 21 हाथियों के लिए साप्ताहिक 'हाथी रेजुविनेशन' (पुनर्योवनीकरण) कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो आज अपने सातवें और अंतिम दिन के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सात दिवसीय विशेष शिविर में नर, मादा और शावक सभी हाथियों ने एक-साथ मिल जुल कर समय बिताया। प्रत्येक दिवस के साथ समापन समारोह के अवसर पर हाथियों को उनकी पसंद के विशेष खाद्य पदार्थ जैसे– सेब, तरबूज, केला, गुड़ के लड्डू, गन्ना और पौष्टिक दलिया प्रचुर मात्रा में खिलाए गए। कार्यक्रम के दौरान वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी तथा जबलपुर वेटरनरी कॉलेज से आए विशेषज्ञ दल की उपस्थिति में सभी हाथियों का विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं आवश्यक सैंपल भी कलेक्ट किए गए, जिससे उनकी शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य की पुख्ता निगरानी सुनिश्चित हो सके। साथ ही महावतों का भी खेल विभ्भिन दिवस में अयोजित हुआ एवं पुरस्कार वितरण किया गया ।समापन कार्यक्रम में उप संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व, वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी, तथा जबलपुर वेटरनरी कॉलेज से आए विशेषज्ञ दल , सहायक संचालक पन्ना, सहायक संचालक मंडला, अधीक्षक केन घड़ियाल खजुराहो, एवं समस्त परिक्षेत्र अधिकारी, वन अमला, समस्त हाथी महावत, तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सरपंच एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

यह आयोजन वन एवं वन्यजीव प्रेमियों तथा वन विभाग के लिए बेहद सार्थक, प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण साबित हुआ।

जनसंवाद शिविर का आयोजन कल

नरसिंहपुर। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिले में प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने तथा नागरिकों की समस्याओं का मौके पर निराकरण सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर पहल की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार 3 अक्टूबर को उत्कृष्ट विद्यालय चावरपाठा में में जनसंवाद शिविर आयोजित किया जाएगा।

शासकीय हाई स्कूल मुराछ में हुआ नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम



दैनिक रेवांचल टाईम्स, पन्ना। शासकीय हाई स्कूल मुराछ में बुधवार, 30 सितंबर 2026 को पन्ना से आए प्रजापति ब्रह्माकुमारी आश्रम के प्रतिनिधियों एवं अंशू राजा (राघवेंद्र सिंह बुंदेला) के द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संस्था के प्राचार्य रामसेवक सिंह सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्र-छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम में श्री राजेंद्र श्रीवास्तव जी ने विद्यार्थियों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देते हुए नशे से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहानी एवं प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से विद्यार्थियों को नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान छात्र-छात्राओं को प्रतिज्ञा दिलाई गई कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे तथा अपने माता-पिता, भाई-बहन और गांव के अन्य लोगों को भी नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करेंगे। विद्यार्थियों ने नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में प्रजापति ब्रह्माकुमारी आश्रम की ओर से संस्था के प्राचार्य रामसेवक सिंह को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके पश्चात राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

पन्ना पुलिस की बड़ी कार्रवाई

180 लीटर अवैध देशी शराब एवं लग्जरी कार सहित कुल 9 लाख का मशरूका जप्त

दो आरोपी गिरफ्तार, चार फरार आरोपियों की तलाश जारी



दैनिक रेवांचल टाईम्स, पन्ना। पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती वंदना चौहान के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब के कारोबार एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली पन्ना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर एक सफेद रंग की कार से भारी मात्रा में अवैध देशी शराब का परिवहन करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 180 लीटर अवैध देशी शराब एवं शराब परिवहन में प्रयुक्त कार सहित कुल ?9,00,000/- का मशरूका जप्त किया गया है। दिनांक 29.09.2026 को थाना कोतवाली पन्ना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति सफेद रंग की कार में अवैध शराब लेकर देवेन्द्रनगर से बिक्री हेतु पन्ना की ओर आ रहे हैं। सूचना की तस्दीक एवं वैधानिक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रोहित कुमार मिश्रा के निर्देशन में तत्काल पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पन्ना-सतना रोड, सकरिया की ओर रवाना हुई। इसी दौरान ग्राम छापर टेक, पन्ना-देवेन्द्रनगर आम रोड पर देवेन्द्रनगर-सकरिया की ओर से एक सफेद रंग की कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम को देखकर कार चालक द्वारा वाहन को मोड़कर छापर गांव की ओर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम ने तत्परता एवं मुस्तैदी से पीछा करते हुए नर्सरी गेट के पास घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया।

तलाशी एवं जप्त मशरूका : नियमानुसार वाहन की तलाशी लेने पर कार की सीटों के नीचे एवं पीछे डिग्गी में खाकी रंग के कार्टून रखे मिले। काटूर्नों की जांच करने पर उनमें अवैध देशी शराब पाई गई। अवैध देशी शराब झ 1,000 क्वार्टर प्रत्येक क्वार्टर झ 180 एमएल कुल मात्रा झ 180 लीटर अनुमानित कीमत झ ?1,00,000/- शराब परिवहन में प्रयुक्त सफेद रंग की कार क्रमांक ट्ढ35 उअ 3672 वाहन की अनुमानित कीमत झ ?8,00,000/- कुल जप्त मशरूका झ लगभग ?9,00,000/-

गिरफ्तार आरोपियों के नाम : 1. सौरभ विश्वकर्मा पिता रमेश विश्वकर्मा, उम्र 31 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 11, पुराने आर.पी. स्कूल के पीछे, आगरा मोहल्ला पन्ना, थाना कोतवाली पन्ना – वाहन चालक। 2. उमेश रैकवार पिता दीनदयाल रैकवार, उम्र 30 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 10, नट के हनुमान मंदिर के पास, आगरा मोहल्ला पन्ना, थाना कोतवाली पन्ना।

फरार आरोपियों के नाम : प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है– आरोपियों द्वारा बिना किसी वैध लाइसेंस के अवैध शराब का परिवहन किया जाना पाए जाने पर उनके विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजे जाने की कार्रवाई की गई। प्रकरण में फरार आरोपियों की तलाश एवं अन्य बिंदुओं पर विवेचना जारी है।

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका : उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रोहित कुमार मिश्रा के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक आईमात से, सुरेश कुमार, मनीष कश्यप, राजेश कुमार, संतोष तोमर, खेमचन्द्र राय एवं आरक्षक फेरन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित

दैनिक रेवांचल टाइम्स नरसिंहपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले में विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं द्वारा जनजागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, वित्तीय साक्षरता, साइबर सुरक्षा, नशामुक्ति तथा युवाओं को कैरियर एवं उद्यमिता के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों एवं नागरिकों को शासन की योजनाओं की जानकारी देने के साथ सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक किया गया। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र नरसिंहपुर द्वारा शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय नरसिंहपुर में विद्यार्थियों के लिए कैरियर एवं उद्यमिता काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों को स्वरोजगार, उद्यमिता एवं उद्योग स्थापना के अवसरों की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, एमएसएमई प्रोत्साहन योजना एवं स्टार्टअप नीति-2025 के तहत उपलब्ध ऋण एवं प्रोत्साहन सुविधाओं तथा उद्योग स्थापना की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।

Manufacturer of t-shirts & lowers Mo. 9174614421, 9406763810
CHANDRAKALA TEXTILES
सभी प्रकार की टी-शर्ट ऑर्डर पर बनाई और प्रिंट की जाती हैं और स्पोर्ट्स सबलिमेसन जर्सी बनाई जाती हैं।
Address : shop no 151, jabalpur fashion design cluster market Lema garden Gohalpur jabalpur 482001

सरकारी नाली पर पक्का निर्माण? बम्हनी बंजर में कथित अतिक्रमण ने नगर परिषद की निगरानी पर खड़े किए सवाल

बम्हनी बंजरे कथित अतिक्रमण नगर परिषद सरकारी नाली पर पक्का निर्माण? कथित अतिक्रमण ने नगर परिषद की निगरानी पर खड़े किए सवाल

नाली की भूमि को निर्माण में शामिल करने का आरोप; कॉलम-बीम के बाद लेंटर की तैयारी की शिकायत, अब सीमांकन और स्थल जांच की मांग



दैनिक रेवांचल टाईम्स, मंडला। बम्हनी बंजर। नगर परिषद बम्हनी बंजर क्षेत्र में एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के सामने स्थित शासकीय नाली की भूमि पर कथित रूप से पक्का निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार पूनम साड़ी सेल के सामने स्थित नाली के हिस्से को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। आरोप है कि सुरभि साड़ी शोरूम के संचालक सौरव अग्रवाल द्वारा कराए जा रहे निर्माण में सार्वजनिक नाली के हिस्से को अंदर लेते हुए कॉलम और बीम खड़े किए जा रहे हैं तथा आगे लेंटर डालने की तैयारी है। हालांकि निर्माण वास्तव में निजी स्वामित्व की भूमि पर है या नगर परिषद की नाली अथवा सार्वजनिक भूमि के किसी हिस्से को इसमें शामिल किया गया है, इसकी पुष्टि अधिकृत सीमांकन और नगर परिषद की जांच से ही हो सकेगी। आठ वर्ष पहले इसी स्थान से हटाया गया था अतिक्रमण? स्थानीय लोगों का दावा है कि करीब आठ वर्ष पहले तत्कालीन एसडीएम मंडला के निर्देश पर इसी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी और मौके से चार ठेले हटाए गए थे। यदि पुरानी कार्रवाई इसी नाली अथवा सार्वजनिक भूमि से संबंधित थी तो नगर परिषद के रिकॉर्ड में इसकी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। पुराने सीमांकन और अतिक्रमण कार्रवाई के अभिलेख वर्तमान विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सबसे पहले सीमांकन—निजी जमीन कहां, सरकारी नाली कहां? पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण सवाल भूमि की वास्तविक सीमा का है। नगर परिषद और राजस्व अमले को मौके पर उपलब्ध नक्शे, रिकॉर्ड और निर्माण की स्थिति का मिलान कर यह स्पष्ट करना होगा कि निर्माण पूरी तरह निजी भूमि के भीतर हो रहा है या सार्वजनिक नाली की भूमि का कोई हिस्सा भी इसमें शामिल किया गया है। यदि निर्माण निजी भूमि पर और स्वीकृत अनुमति के अनुरूप पाया जाता है तो आरोपों की स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यदि जांच में नाली अथवा सार्वजनिक भूमि पर निर्माण पाया जाता है तो यह भी स्पष्ट करना होगा कि निर्माण किस अनुमति के आधार पर किया जा रहा था।

कानून भी कहता है—नाली के ऊपर निर्माण के लिए जरूरी है परिषद की लिखित सहमति- मध्यप्रदेश नगरपालिकाएं अधिनियम, 1961 में नगर परिषद में निहित सीवर, नाली, पुलिया अथवा गटर के ऊपर नए निर्माण या पुनर्निर्माण को लेकर स्पष्ट प्रावधान हैं। ऐसे निर्माण के लिए परिषद की लिखित सहमति आवश्यक होती है। इसलिए इस मामले में यह भी जांच का विषय है कि संबंधित निर्माण के लिए नगर परिषद से नक्शा अथवा निर्माण अनुमति ली गई है या नहीं और यदि कोई अनुमति जारी हुई है तो उसमें नाली तथा निर्माण की सीमा किस प्रकार दर्ज है।

नाली दबेगी तो जल निकासी पर क्या होगा असर?- सार्वजनिक नाली केवल जमीन का एक हिस्सा नहीं बल्कि नगरीय जल निकासी व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि यदि नाली के मूल स्वरूप या उसकी चौड़ाई को प्रभावित किया गया तो बारिश और गंदे पानी की निकासी में परेशानी पैदा हो सकती है। इसलिए निरीक्षण में केवल यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि कॉलम कहां खड़े हैं, बल्कि नाली की मूल चौड़ाई, पानी के प्रवाह, सफाई के लिए उपलब्ध पहुंच और भविष्य में रखरखाव की व्यवस्था भी देखी जानी चाहिए।

मामला नगर परिषद के संज्ञान में, अब स्थल निरीक्षण का इंतजार- उपलब्ध जानकारी के अनुसार मामला नगर परिषद की मुख्य नगर पालिका अधिकारी मीना पटेल के संज्ञान में पहुंचाया गया है। उनका कहना बताया गया है कि कर्मचारी को मौके पर भेजकर स्थल का निरीक्षण कराया जाएगा। अब निगाह इस बात पर है कि निरीक्षण में नाली और निर्माण की वास्तविक सीमा का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है और मौके की स्थिति के आधार पर परिषद क्या निर्णय लेती है।

निरीक्षण तक निर्माण आगे बढ़ा तो जिम्मेदारी किसकी?- शिकायत करने वालों का आरोप है कि नगर परिषद तक मामला पहुंचने के बावजूद मौके पर निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है और कॉलम-बीम के बाद लेंटर डालने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि विवादित निर्माण की स्थिति स्पष्ट होने तक नगर परिषद ने मौके पर क्या कदम उठाया? यदि निर्माण वैध है तो दस्तावेजों से स्थिति साफ की जानी चाहिए और यदि प्रथम दृष्टया सार्वजनिक भूमि अथवा नाली प्रभावित होती दिखाई देती है तो नियमानुसार तत्काल कार्रवाई पर निर्णय होना चाहिए।

इन दस्तावेजों से साफ हो सकती है पूरी तस्वीर - नगर परिषद यदि संबंधित भूखंड का स्वामित्व रिकॉर्ड, स्वीकृत नक्शा, भवन निर्माण अनुमति, नाली का नगर परिषद रिकॉर्ड, पुराना सीमांकन तथा पूर्व में हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दस्तावेजों का मिलान करती है तो विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

रेवाँचल टाईम्स के सीधे सवाल- जिस स्थान पर निर्माण चल रहा है उसकी वास्तविक सीमा क्या है? नाली नगर परिषद के रिकॉर्ड में कितनी चौड़ी और कहां तक दर्ज है? क्या संबंधित निर्माण का नक्शा स्वीकृत है? क्या नाली के ऊपर अथवा उसके हिस्से को शामिल कर निर्माण करने की कोई लिखित अनुमति दी गई है? यदि नहीं, तो निर्माण प्रारंभ होने के समय नगर परिषद का मैदानी अमला कहां था? और यदि निर्माण पूरी तरह वैध है तो परिषद दस्तावेज सार्वजनिक कर विवाद को समाप्त क्यों नहीं करती?

आरोप की पुष्टि सीमांकन और दस्तावेजों की जांच से ही- फिलहाल संबंधित शोरूम संचालक पर लगाए गए अतिक्रमण के आरोप की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। केवल निर्माण होते दिखाई देने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध हो गया है। इसके लिए नगर परिषद एवं संबंधित राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर स्थल का सीमांकन और निर्माण अनुमति की जांच जरूरी है। अब नजर नगर परिषद की आगामी कार्रवाई पर है। स्थल निरीक्षण और रिकॉर्ड की जांच के बाद यह साफ होना चाहिए कि निर्माण निजी भूमि की सीमा में है या सार्वजनिक नाली का कोई हिस्सा प्रभावित हो रहा है। यदि अतिक्रमण नहीं है तो स्थिति स्पष्ट की जाए और यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो निर्माण पूरा होने का इंतजार किए बिना नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

खेरीमाल में टायर फटते ही खुला संदिग्ध पशु परिवहन का मामला, वाहन में मिले करीब 16 भैंस-पड़ा

खेरीमाल में टायर फटते ही खुला संदिग्ध पशु परिवहन का मामला, वाहन में मिले करीब 16 भैंस-पड़ा



दैनिक रेवांचल टाईम्स मंडला। जिले में पशुओं के कथित अवैध परिवहन को लेकर एक और मामला सामने आया है। चाबी चौकी क्षेत्र के खेरीमाल के पास डिंडोरी की ओर से मंडला की तरफ आ रहे एक वाहन का टायर फटने के बाद उसमें बड़ी संख्या में पशु लदे होने की जानकारी सामने आई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वाहन में करीब 16 नग भैंस-पड़ा मिले हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीण, बजरंग दल से जुड़े लोग और समाजसेवी मौके पर पहुंचे तथा पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में लेकर चाबी चौकी में सुरक्षित खड़ा कराया है। चालक और उसके साथ मौजूद बताए जा रहे अन्य लोग वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। अब पुलिस पशुओं के परिवहन से जुड़े दस्तावेज, वाहन मालिक, चालक और पशुओं के स्रोत व गंतव्य की जांच कर रही है।

सुबह 5 बजे मिली सूचना, ग्रामीणों ने किया पीछा- जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5 बजे ग्रामीणों को सूचना मिली कि डिंडोरी की ओर से मंडला की तरफ एक वाहन में बड़ी संख्या में पशुओं को भरकर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों, बजरंग दल से जुड़े लोगों और समाजसेवियों ने वाहन का पीछा किया।

खेरीमाल के पास फटा टायर, वाहन छोड़कर भागे लोग- बताया गया कि वाहन मेहंदवानी तिराहा पार कर खेरीमाल के आसपास पहुंचा था। इसी दौरान वाहन का ड्राइवर साइड का अगला टायर फट गया और वाहन आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद चालक और उसके साथ मौजूद बताए जा रहे कुछ लोग वाहन छोड़कर मौके से भाग निकले। ग्रामीणों ने तत्काल चाबी चौकी पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को कब्जे में लिया। वाहन की जांच के दौरान उसमें बड़ी संख्या में भैंस-पड़ा लदे मिले। उपलब्ध जानकारी में इनकी संख्या करीब 16 बताई गई है।

MP 20 GB 1636 नंबर का वाहन- उपलब्ध जानकारी के अनुसार पशुओं का परिवहन MP 20 GB 1636 नंबर के वाहन से किया जा रहा था। वाहन को चाबी चौकी में खड़ा कराया गया है। पुलिस द्वारा वाहन के पंजीयन, स्वामित्व और परिवहन से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

ग्रामीणों की सक्रियता से पुलिस तक पहुंचा मामला- इस घटनाक्रम में चाबी क्षेत्र के राजेश यादव, गोविंद कुरुम, संगम यादव, लक्ष्मण साहू, इमरत झरिया, मोहन झरिया और हेमराज साहू सहित अन्य ग्रामीणों एवं समाजसेवियों की सक्रियता बताई जा रही है। ग्रामीणों ने वाहन के संबंध में जानकारी मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी।

पशु कहां से आए और कहां ले जाए जा रहे थे?- जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अब पशुओं का स्रोत और उनका गंतव्य है। पशुओं को कहां से लादा गया, किसके द्वारा भेजा गया, कहां पहुंचाया जाना था और परिवहन के लिए आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे या नहीं—इन सवालों के जवाब चालक, वाहन मालिक और संबंधित दस्तावेजों की जांच से सामने आएंगे।

पशु परिवहन के लिए भी निर्धारित हैं नियम- देश में पशुओं के परिवहन और उनके साथ क्रूरता रोकने के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 तथा Transport of Animals Rules, 1978 सहित संबंधित नियम लागू हैं। इसलिए इस मामले में पशुओं की स्थिति, वाहन में उपलब्ध स्थान, परिवहन की परिस्थितियां और लागू दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण होगी।

कार्रवाई के बावजूद अवैध परिवहन पर उठ रहे सवाल- जिले में समय-समय पर संदिग्ध अथवा अवैध पशु परिवहन के मामलों में कार्रवाई सामने आती रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों और डिंडोरी-मंडला मार्ग से गुजरने वाले पशु वाहनों की निगरानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते वाहन की जानकारी नहीं मिलती तो वह आगे निकल सकता था। हालांकि इस घटना के आधार पर किसी व्यापक तस्करी नेटवर्क के अस्तित्व का निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। यदि पुलिस जांच में अन्य वाहन, व्यक्ति अथवा लेन-देन से जुड़ी कड़ियां सामने आती हैं तभी नेटवर्क की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

चालक का फरार होना बढ़ा रहा संदेह, लेकिन जांच से तय होगा अपराध- वाहन रुकने के बाद चालक और अन्य लोगों के मौके से चले जाने की जानकारी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुलिस को चालक की पहचान और तलाश के साथ वाहन मालिक से पूछताछ कर यह पता लगाना होगा कि पशुओं का परिवहन किस उद्देश्य से किया जा रहा था। केवल पशुओं का वाहन में मिलना अपने आप तस्करी के उद्देश्य को साबित नहीं करता।

अब इन सवालों पर टिकी जांच - वाहन का वास्तविक मालिक कौन है? चालक कौन था? पशुओं को कहां से लाया गया था? उन्हें कहां पहुंचाया जाना था? परिवहन के लिए आवश्यक वैधानिक दस्तावेज मौजूद थे या नहीं? वाहन में पशुओं को निर्धारित नियमों के अनुरूप रखा गया था या नहीं? इन सभी बिंदुओं की जांच के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर सामने आ सकेगी।

पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगा मामला- फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार वाहन पुलिस के कब्जे में है और मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फरार चालक और अन्य व्यक्तियों की पहचान, पशुओं के परिवहन का उद्देश्य तथा दस्तावेजों की वैधता की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर संबंधित धाराओं में आगे की कार्रवाई तय होगी।

किताबों से दोस्ती, नेतृत्व की तैयारी: बीजाडांडी में 50 पुस्तकालय रिसोर्स बच्चों की कार्यशाला

किताबों से दोस्ती, नेतृत्व की तैयारी: बीजाडांडी में 50 पुस्तकालय रिसोर्स बच्चों की कार्यशाला

10 प्राथमिक शालाओं के बच्चों ने लिया भाग, पठन संस्कृति के साथ अभिव्यक्ति और नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर जोर



दैनिक रेवाँचल टाईम्स - मंडला, बीजाडांडी। बच्चों में किताबों के प्रति रुचि बढ़ाने और विद्यालयीन पुस्तकालयों को जीवंत सीखने के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एकलव्य फाउंडेशन द्वारा ओरेकल के वित्तीय सहयोग से संचालित जीवंत पुस्तकालय कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार, 30 सितंबर को एक दिवसीय पुस्तकालय रिसोर्स बच्चों की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला प्राथमिक शाला चरगांव माल एवं बीआरसी कार्यालय बीजाडांडी में आयोजित हुई। इसमें विकासखंड की चयनित 10 प्राथमिक शालाओं से पांच-पांच बच्चों सहित कुल 50 बच्चों ने सहभागिता की।

10 प्राथमिक शालाओं से पहुंचे बच्चे- कार्यशाला में प्राथमिक शाला भटा डुंगरिया, बरौंची, विजयपुर, पिपरिया रैय्यत, चरगांव माल, सलैया माल, घोंटा, घुघरी, डुंगरिया और पिपरिया (बुदरा) के बच्चों ने हिस्सा लिया।

सिर्फ किताब पढ़ना नहीं, पुस्तकालय की जिम्मेदारी भी सीखेंगे बच्चे

कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों को पुस्तकालय रिसोर्स के रूप में उनकी भूमिका, जिम्मेदारी और जवाबदेही से परिचित कराना था, ताकि विद्यालयों में पुस्तकालय की गतिविधियों को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाया जा सके। बच्चों को पुस्तकों को व्यवस्थित रखने, अपनी पसंद की पुस्तक चुनने और दूसरे बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करने सहित पुस्तकालय संचालन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई। विशेष जोर इस बात पर रहा कि बच्चे केवल पुस्तकालय के पाठक न रहें, बल्कि उसकी गतिविधियों में सक्रिय भागीदार और नेतृत्वकर्ता भी बनें।

कविता, बुक रेस और किताब चर्चा ने बढ़ाया उत्साह

कार्यशाला को रोचक बनाने के लिए कविता गायन, किताब-अखबार, मेरे जैसे कौन , किताबों को प्रदर्शित करने के तरीके, बुक रेस और किताब चर्चा जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं। इन गतिविधियों ने बच्चों को किताबों से सहज रूप से जुड़ने के साथ अपने विचार व्यक्त करने, सवाल पूछने और दूसरे बच्चों के विचार सुनने का अवसर दिया।

पठन के साथ अभिव्यक्ति और नेतृत्व क्षमता पर फोकस

कार्यशाला में बच्चों की स्वतंत्र पठन क्षमता, भाषा एवं अभिव्यक्ति कौशल, रचनात्मक सोच, तार्किक समझ और नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में सहयोग, संवाद और समूह में सीखने की भावना को भी प्रोत्साहित किया गया।

किताबों के संग्रह से आगे जीवंत पुस्तकालय की अवधारणा

एकलव्य फाउंडेशन की इस पहल का उद्देश्य विद्यालयीन पुस्तकालयों को केवल किताबों के संग्रह तक सीमित रखने के बजाय बच्चों के लिए पढ़ने, सीखने, सोचने, कल्पना करने और अपनी बात कहने का जीवंत माध्यम बनाना है। पुस्तकालय रिसोर्स बच्चों को जिम्मेदारी देकर विद्यालय स्तर पर अन्य बच्चों को भी पुस्तकों से जोड़ने और नियमित पठन की संस्कृति विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

शिक्षा तंत्र के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद

कार्यशाला में बीआरसी मनोज चंदेल, बीएसी, सीएसी, प्राथमिक शाला चरगांव माल के शिक्षक श्री झारिया, दो अतिथि शिक्षक, तीन यूथ साथी तथा एकलव्य टीम बीजाडांडी के साथी उपस्थित रहे। आयोजन से जुड़े लोगों के अनुसार बीजाडांडी शिक्षा तंत्र द्वारा इस प्रकार के शैक्षणिक नवाचारों और बच्चों को केंद्र में रखकर आयोजित गतिविधियों में लगातार सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

बच्चे पढ़ेंगे, समझेंगे और दूसरों को भी किताबों से जोड़ेंगे

पुस्तकालय रिसोर्स बच्चों की यह पहल विद्यालय में बच्चों को जिम्मेदारी देने के साथ उनमें नेतृत्व विकसित करने का प्रयास भी है। इससे किताब और बच्चे के बीच रिश्ता मजबूत होने के साथ विद्यालय में सामूहिक पठन की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सुभाष वार्ड में सेवा संकल्प अभियान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका का सम्मान, पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

सुभाष वार्ड में ह्यसेवा संकल्प अभियान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका का सम्मान



दैनिक रेवाँचल टाईम्स - मंडला। सुभाष वार्ड स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक-1 में ह्यसेवा संकल्प अभियानह्ल के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद मंजू कछवाहा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सविता चौरसिया एवं सहायिका का सम्मान करते हुए केंद्र के माध्यम से संचालित गतिविधियों की सराहना की।

हितग्राहियों को योजनाओं से जुड़ने के लिए किया प्रेरित- कार्यक्रम के दौरान पार्षद मंजू कछवाहा ने आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी हितग्राहियों को दी। उन्होंने महिलाओं और बच्चों से नियमित रूप से केंद्र से जुड़ने तथा पात्रता के अनुसार शासन की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।

पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर हुआ संवाद- कार्यक्रम में उपस्थित हितग्राहियों को पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। केंद्र से मिलने वाली सेवाओं का नियमित लाभ लेने और बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए भी जागरूक किया गया।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का सम्मान- सेवा संकल्प अभियान के अवसर पर पार्षद मंजू कछवाहा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सविता चौरसिया और सहायिका का सम्मान किया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियों में स्थानीय सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश- कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी परिसर में पौधारोपण भी किया गया। उपस्थित लोगों ने पौधों की देखभाल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया।

आंगनबाड़ी केंद्र को जनजागरूकता से जोड़ने का प्रयास- आयोजन के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र की नियमित सेवाओं के साथ हितग्राहियों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने, पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया।

नागपुर-मंडला फोर्ट नियमित ट्रेन की उम्मीद को झटका: RTI जवाब में प्रस्ताव और रेलवे बोर्ड से पत्राचार नहीं होने की जानकारी



दैनिक रेवाँचल टाईम्स - मंडला। नागपुर और मंडला के बीच सीधी नियमित रेल सेवा की उम्मीद लगाए बैठे यात्रियों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिला एक जवाब महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रहा है। उपलब्ध फळक जवाब के अनुसार ट्रेन क्रमांक 08841/08842 नागपुर (इतवारी)-मंडला फोर्ट को नियमित अथवा स्थायी रूप से चलाने के संबंध में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय के वाणिज्य विभाग के स्तर पर प्रस्ताव तैयार किए जाने की जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनवरी 2026 में इसी रूट पर विशेष ट्रेन चलने के बाद क्षेत्र के यात्रियों में नागपुर और मंडला के बीच सीधी ट्रेन को नियमित किए जाने की उम्मीद बढ़ी थी। अब फळकजवाब सामने आने के बाद यात्रियों और रेल सुविधा के लिए सक्रिय लोगों की ओर से जनप्रतिनिधियों तथा रेलवे प्रशासन से ठोस पहल की मांग उठ रही है।

RTI में क्या पूछा, रेलवे के जवाब में क्या आया?- उपलब्ध जानकारी के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दिए गए जवाब पत्र क्रमांक C/SECR/BSP/RTI/00361/1/26-27/808 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय की ओर से ट्रेन के नियमित संचालन से जुड़े बिंदुओं पर जानकारी दी गई है। फळक जवाब के अनुसार एएउफ मुख्यालय के वाणिज्य विभाग में इस ट्रेन को स्थायी रूप से चलाने के संबंध में कोई प्रस्ताव, नोट, व्यवहार्यता रिपोर्ट अथवा औचित्य तैयार किए जाने की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार नियमितीकरण अथवा विस्तार के संबंध में रेलवे बोर्ड को पत्र अथवा अनुशंसा भेजे जाने की जानकारी भी नहीं दी गई है।

जनवरी में चली थी नागपुर-मंडला फोर्ट स्पेशल ट्रेन- वर्ष 2026 में मकर संक्रांति के अवसर पर ट्रेन क्रमांक 08841/08842 को नागपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन और मंडला फोर्ट के बीच विशेष ट्रेन के रूप में सीमित अवधि के लिए संचालित किया गया था। इस ट्रेन ने मंडला और नागपुर को नैनपुर, केवलारी, सिवनी, छिंदवाड़ा, सौंसर और सावनेर की ओर से सीधी रेल कनेक्टिविटी दी। सीमित अवधि के इस संचालन के बाद क्षेत्र में इसे नियमित करने की मांग उठना स्वाभाविक था। अब सवाल यह है कि इस मांग को रेलवे की औपचारिक प्रस्ताव प्रक्रिया तक पहुंचाने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।

सवाल सीधा-जब प्रस्ताव ही नहीं तो नियमित ट्रेन की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी?- RTI जवाब के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रक्रिया का है। यदि ट्रेन को नियमित करने के लिए संबंधित रेलवे स्तर पर कोई औपचारिक प्रस्ताव, व्यवहार्यता परीक्षण अथवा रेलवे बोर्ड को अनुशंसा ही नहीं भेजी गई है, तो स्थायी सेवा की मांग आगे किस स्तर पर और किस प्रक्रिया से बढ़ाई जाएगी? यात्रियों की मांग है कि रेलवे इस रूट पर यात्री संख्या, संभावित राजस्व, परिचालन व्यवहार्यता, रेक उपलब्धता और समय-सारणी का अध्ययन कर स्थिति स्पष्ट करे।

सांसद से भी ठोस पहल की अपेक्षा- RTI जवाब सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि मंडला संसदीय क्षेत्र की ओर से इस ट्रेन को नियमित कराने के लिए रेलवे के समक्ष अब तक क्या औपचारिक प्रयास किए गए हैं और आगे क्या पहल प्रस्तावित है। किसी सांसद के पास स्वयं ट्रेन शुरू करने का प्रशासनिक अधिकार नहीं होता, लेकिन क्षेत्रीय मांग को रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के समक्ष उठाना, पत्राचार करना और संबंधित रेलवे अधिकारियों से प्रस्ताव तैयार करने की मांग करना जनप्रतिनिधित्व के दायरे में आने वाली महत्वपूर्ण पहल हो सकती है।

सेवा संकल्प यात्रा के दूसरे दिन हितग्राहियों से सीधा संवाद, मंडला से डिंडौरी के लिए हुई रवाना



दैनिक रेवाँचल टाईम्स - मंडला। भारतीय जनता पार्टी के सेवा संकल्प अभियान के तहत निकाली जा रही कलश यात्रा के मंडला प्रवास के दूसरे दिन विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। यात्रा के दौरान रामनगर, घुघरी और सलवाह में ग्रामीणों तथा विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद किया गया। यात्रा का नेतृत्व गुजरात के बारडोली लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रभुभाई वसावा कर रहे हैं। दूसरे दिन यात्रा की शुरूआत होटल किंगफिशर से हुई, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने कलश में मां नर्मदा का जल अर्पित किया। इसके बाद यात्रा रामनगर की ओर रवाना हुई।

बायपास पर पुष्पवर्षा, पदमी में शहीद उमराव सिंह लोधी को नमन- बायपास स्थित बब्बू ढाबा के सामने बाइकर्स और कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर सेवा यात्रियों का स्वागत किया। इसके बाद यात्रा पदमी चौराहा पहुंची, जहां शहीद उमराव सिंह लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान यात्रा में शामिल युवाओं को शहीद उमराव सिंह लोधी के जीवन और योगदान के बारे में जानकारी दी गई। यहां से यात्रा रामनगर की ओर आगे बढ़ी।

रामनगर महल में दिखी जनजातीय संस्कृति की झलक- रामनगर चौराहे पर अंजनिया मंडल के कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद यात्रा गोंड शासन से जुड़े ऐतिहासिक रामनगर महल पहुंची। यहां स्थानीय परंपराओं और जनजातीय संस्कृति के अनुरूप यात्रियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान गोंड राजवंश के कुल देवी-देवताओं की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। यात्रा में शामिल पदाधिकारियों और बाइकर्स ने रामनगर महल का भ्रमण भी किया।

ग्रामीणों से पूछा—योजनाओं से जीवन में क्या बदलाव आया?- रामनगर में ग्रामीणों से संवाद के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ को लेकर बातचीत की गई। यात्रा में शामिल प्रतिनिधियों ने हितग्राहियों से उनके अनुभव जाने और योजनाओं से जीवन में आए बदलावों के बारे में जानकारी ली।

घुघरी में लाभार्थियों से सीधा संवाद- रामनगर के बाद यात्रा घुघरी के लिए रवाना हुई। घुघरी पहुंचने से करीब 10 किलोमीटर पहले युवा कार्यकर्ताओं और बाइकर्स ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद यात्रा घुघरी में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में पहुंची। यहां सांसद प्रभुभाई वसावा सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने हितग्राहियों से सीधा संवाद किया। आयोजकों के अनुसार हितग्राहियों से यह जानने का प्रयास किया गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से पहले उनकी स्थिति क्या थी और लाभ मिलने के बाद उनके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आए। इस दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों के अनुभवों पर चर्चा की गई।

सलवाह में महिला हितग्राही सम्मेलन- घुघरी के बाद सेवा संकल्प यात्रा सलवाह मंडल पहुंची, जहां महिला हितग्राही सम्मेलन आयोजित किया गया। महिलाओं से संवाद कर उनसे पूछा गया कि उन्हें किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और किन योजनाओं का लाभ अभी उन तक नहीं पहुंच पाया है। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने उज्ज्वला गैस योजना, किसान सम्मान निधि, लाड़ली बहना योजना और पेंशन योजना सहित विभिन्न योजनाओं से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।

मंडला का प्रवास पूरा, डिंडौरी जिले के लिए रवाना- सलवाह मंडल में आयोजित कार्यक्रम के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा और जिला यात्रा प्रभारी विकास यादव ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ यात्रा को डिंडौरी जिले के अमरपुर के लिए रवाना किया।

मोहगांव में FLN प्रशिक्षण का प्रथम चरण संपन्न, 103 शिक्षकों ने सीखे गतिविधि आधारित शिक्षण के तरीके



दैनिक रेवाँचल टाईम्स - मंडला। राज्य शिक्षा केंद्र के निदेर्शानुसार विकासखंड मोहगांव में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी FLN (Foundational Literacy and Numeracy) प्रशिक्षण का प्रथम चरण संपन्न हुआ। जनपद शिक्षा केंद्र के तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण में कुल 103 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का आयोजन कलेक्टर राहुल नामदेव धोते, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी शाश्वत सिंह मीणा तथा जिला परियोजना समन्वयक अशोक शुक्ला के निर्देशन में किया गया।

कक्षा 1 और 2 की बुनियादी शिक्षा पर विशेष फोकस- प्रशिक्षण में विशेष रूप से कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। भोपाल से प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर्स ने शिक्षकों को गतिविधि आधारित शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण को केवल सैद्धांतिक जानकारी तक सीमित न रखते हुए तकनीकी उपकरणों, शिक्षण सहायक सामग्री और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कक्षा में बच्चों को सरल एवं प्रभावी तरीके से पढ़ाने की विधियां समझाई गईं।

तीन कक्षों में चला प्रशिक्षण- माध्यमिक शाला परिसर मोहगांव में प्रशिक्षण के लिए तीन अलग-अलग कक्षों की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक कक्ष में मास्टर ट्रेनर्स ने प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित विषयों और गतिविधियों के माध्यम से FLN की अवधारणाओं तथा उनके व्यावहारिक उपयोग की जानकारी दी।

**बच्चों में कौशल विकसित करने में शिक्षक की अहम भूम